12.19 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

MR. SPEAKER: We now take up the Motion of Thanks on the Presidnt's Address. I would like to inform the House that 14 hours have been allotted by the Business Advisory Committee for this debate and we must try to stick to it because we have a very heavy schedule of legislative and other work. Members present in the House, who desire to move their amendments to the Motion of Thanks may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the amendments they would like to move. I call upon Shri Yagya Datt Sharma to move the motion.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Sir, I draw your attention to Rule 18 which states:

> "Amendments may be moved to such Motion of Thanks in such form as may be considered appropriate by the Speaker."

I humbly submit that the form of the amendment has to be determined by you and not the content of the amendment is to be decided by you. Accordingly, I had given notice of an amendment referring to the serious failure of the Presidential Address in appealing for clemency for Mr. Bhutto. The amendment has not been circulated. Therefore, I am wrongfully debarred from moving this important amendment. I would request you once again that, since you can control only the form of the amendment and not the contents of the subject matter, kindly allow me to move my amendment, wherein I have referred to the failure of the Presidential Address to appeal to the President of Pakistan for clemency to Mr. Bhutto, especially in view of the rising feelings within our own country and the world opinion with respect to it. Sir, I submit that no discourtesy has been shown to Pakistan and our friendly relations are not at all being jeopardised thereby. So many countries are appealing and, therefore, it cannot be said that my amendment reflects in any way discourtesy to a foreign nation, or is repugnant or harmful to our relations with Pakistan.

MR. SPEAKER: I will look into it again and announce the decision.

श्री यज्ञदत्त शर्मा (गुरदासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने 19 फरवरी, 1979 को संसद की एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के भाषण के साथ ही संसद् के नये साल के सम्पूर्ण कार्यक्रम की शुरूआत होती है । महोदय, मैं यहां एक बात पर खेद प्रकट करना चाहूंगा कि मेरे कुछ मित्रों ने इस भाषण का बहिष्कार किया है । मुझे उनकी इस बात का औचित्य प्रतीत नहीं होता है । इसलिये मैं इस पर खेद प्रकट करता हूं । अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का इस समय का भाषण विषय वस्तु की दृष्टि से और विषयों के विश्लेषण और उसकी व्याख्या की दृष्टि से अपने अन्दर ऐसी विशेषता रखता था जिसमें दल की कहानी कम थी, देश का रेखा चित्र अधिक ऊपर आता था । इसमें कोई संदेह नहीं कि संसद में मित्रों ने उस भाषण में संशोधन दिये हैं, उन्हें देने चाहिये । उनक इस अधिकार का मैं आदर करता हूं । संसदीय प्रणाली में यह उनका अधिकार है और मैं समझता हूं आदरणीय है । परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा इस संसदीय प्रणाली में विषयों के ऊपर विवाद की छूट है । हम अपनी बात कहें, उसके ऊपर उस बात का जितना मंथन हो मैं उसका स्वागत करता हूं । मेरा दर्शन है, इस देश की दृष्टि है कि :

"वादे वादे जायते तत्व बोधः"

परन्तु विवाद जब वितंडावाद का रूप ले लेता है तो "वितंडावादे तु केवलम् कंठ शोषः"

उसके अन्दर केवल गला सूखता है । इसलिये उस भाषण में जो विषय रखा गया उसके प्रति अगर आदर और आत्मीयता की दृष्टि से विचार किया जाता और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता तो मुझे अच्छा समझ में आता । परन्तु इस प्रकार का राजनीतिक आचरण संसदीय परम्पराओं को पुष्ट नहीं कर पायेगा । इसलिये मैंने खेद प्रकट किया ।

[श्री यज्ञदत्त शर्मा]

मैं यहां एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आलोचना का हम स्वागत करते हैं। आलोचना यदि नहीं रहेगी तो शायद सत्य का मंथन नहीं हो पायेगा और इस दृष्टि से हमारे दल ने इस देश के अन्दर पहली बार विरोधी दल को मान्यता प्रदान की है।

मैं उस दर्शन का भक्त हूं जिसमें कहा गया है—

जीवन्तु मे निन्दकाः येन प्रसादात् सुविचक्षणोऽहं ।

मेरे निन्दक जीवित रहें, जिनके कारण से मेरी आंखें खुली हैं, जिनके कारण से मेरा मार्ग प्रशस्त है। इसलिये मैं आलोचना का विरोध नहीं करता, आलोचना का स्वागत करता हूं। इसीलिये विरोधी दल को हमने मान्यता प्रदान की है। विरोधी दल को मान्यता प्रदान करने के पीछे हमारा केवल उथला राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। इस जनता दल के महान विचारक नेताओं का उन सुविचक्षण नेताओं, विकर फिनास्कर नेताओं का दृष्टिकोण था कि :

A strong opposition is the real strength of the ruling party.

और इसी नाते से हमने उस विरोधी दल को मान्यता प्रदान की, परन्तु इसके साथ ही यह शर्त भी जुड़ी हुई है कि इस प्रकार का विरोधी दल भी निश्चित रूप से अपोजीशन में उन संसदीय मूल्यों में गहरी आस्था प्रकट करे —

Behave in the retl sense and spirit of democratic values.

तो इस नाते से मैं कहना चाहूंगा कि आज इस नये साल की शुरूआत हम उन शुभारम्भों के साथ करें, उस वृत्ति और दृष्टि के साथ करें जिससे हमारी राष्ट्रीय संसदीय परम्पराएं स्वस्थ हो जायें।

इसी नाते से एक बात यह भी कहना चाहूंगा जैसा मैंने कहा कि आलोचना के हम विरोधी नहीं है, इससे जीवन है, हम एक दूसरे के साथ अपने विषयों को मन्थन करने के लिये पूरे तौर पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करें। हमारे ऊपर जो भी आलोचना हो, उसे सहन करें, एक पक्ष दूसरे को अपनी बात कहने के लिये जितना भी अधिक बल दे सकता हो, बल दे, इसको मैं स्वीकार करता हूं। अगर यह नहीं होगा तो मुझे लगता है कि इससे सदन की सजीवता नष्ट हो जायेगी। इसको बनाये रखने के लिये इसका बल बहुत जरूरी है। कवि ने कहा है कि—

जिन्दगी है कशमकश, मौत है कामिल सकून।

जीवन संघर्ष है और शांति मृत्यु है। यह कहता है कि मेरी बात का विश्वास न हो तो—

शहर में है शोरोगुल मकबरा खामोश है ।

इस नाते से और सदन की सजीवता की दृष्टि से मैं चाहता हूं कि यह हमारे लिये उपादेय है, आवश्यक है कि हर बात का मंथन बहुत गहरे तर्कों के साथ हो, लेकिन उसके साथ ही साथ जिन्दगी का एक नूर भी है, जीवन का आलोक, भी है, प्रकाश भी है। अगर हमारी सारी बात-चीत में वह गरिमा, महानता, मस्तिष्क का आलोक, हृदय की विशालता नहीं रहेगी और सारे व्यवहार में छिछलापन आ जायेगा तो मुझे लगता है कि न हम इन गुत्थियों को सुलझाने की योग्यता रख पायेंगे और न वह धैर्य रख पायेंगे जो बिगड़ी बातों को बनाता है। इस नाते से मैं कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर हम इस मनोवृत्ति से शुरूआत करें कि इस सम्बन्ध में एक विधि-निषेध कायम हो, डूज एंड डोन्ट्स की कोड हो, कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसकी हमें लक्ष्मण-रेखायें खींचनी चाहियें।

आज दो वर्ष बीत गये हैं, तीसरे वर्ष की हम शुरूआत कर रहे हैं, यह मैं बोलने के लिये ही नहीं, केवल इसलिये कहना चाहता हूं कि इससे सदन की मर्यादा रहे। देश के प्रतिनिधि के रूप में भिन्न-भिन्न दलों के द्वारा हम आये हैं, अलग अलग दलों से हम संबंधित हैं, लेकिन इस सदन में आकर बैठकर सब दलों के होते हुए भी हम देश के बड़े कहलाते हैं, देश हमारी ओर देखकर चल रहा है। 70 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी को निभाने की दृष्टि से हमको यहां बैठकर कुछ वैल्यूज क्रीएट करनी हैं, अपने सम्पूर्ण समाज को दिशा प्रदान करनी है, अपने आचरण से मापदंड खड़े करने हैं, इस पर मैं आग्रहपूर्वक बल चाहूंगा।

जनता दल ने लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था प्रकट की है—न केवल वाणी और भाषणों से, बल्कि अपने ठोस कदमों, नीतियों, आचरण और निर्णयों से। जिन कानूनों की प्रतिमा और स्वरूप को बिगाड़ दिया गया था, जैसे पीपल्ज रिप्रेजेन्टेशन एक्ट आदि, उनकी सम्बन्धित धाराओं का परिशोध किया गया है। हमने संविधान में पुनर्जीवन प्रदान किया है, उसको प्राण-रक्षा की है, उसका पुनरुद्धार किया है।

हमने राष्ट्रपति महोदय का चुनाव सब को साथ ले कर, सर्वसम्मति से, किया है। अध्यक्ष महोदय, वह भावनापूर्ण दृश्य मेरी आंखों के सामने आता है, जब आपको इस महान् पद पर सुशोभित करने के लिए आदरणीय श्री मोरारजी देसाई और तत्कालीन विरोधी दल के नेता, श्री यशवन्तराव चव्हाण, आपको बायें-बायें से पकड़ कर अध्यक्ष के आसन की ओर ले जा रहे थे, मानों वे आपके प्रतिष्ठा-पालक बन कर आपको आश्वासन दे रहे थे कि हम इस स्थान की गरिमा को कभी कम नहीं होने देंगे।

हमने यह सब कुछ इस लिए किया है कि लोकतंत्र के भव्य भवन के तोरण द्वार पर जो

महान् मंत्र अंकित है, वह है समन्वय—सब को साथ ले कर चलना । इसीलिए हम ने सब काम सब को साथ ले कर, सब के सहयोग से किये हैं । अपोजीशन को आज इस स्थिति को स्वीकार कर के चलना है, इस नये दृष्टिकोण को अपनाना है कि विरोध के लिए विरोध न हो, हर बात का विरोध न हो, कड़वेपन का विरोध न हो । मैं विरोध चाहता हूं, लेकिन विरोध में हमारी आंखों की चमक मन्द और हृदय का स्नेह सूखने न पाये। जनता दल से नये प्रकार के पोलीटिकल एथिक्स को स्वीकार किया है । उसने चिन्तन, शैली और व्यवहार का आमूल-चूल बदला है, हमारे चिन्तन की धारा बदली है । हम मान कर चलते हैं कि किये का अहंकार न हो । किन्तु, कर्त्तव्य-भावना का विनम्र भाव हम ने कायम रखा है ।

हम ने अपोजीशन को मान्यता प्रदान की है । जब श्री यशवन्तराव चव्हाण को राष्ट्रपति महोदय के पिछले अभिभाषण के समय उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ, और उधर के बेंचिज की ओर से यह बात पायंट आउट की गई, तो प्रधान मंत्री महोदय उसी वक्त खड़े हुए और उन्होंने विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगी कि हम से भूल हुई है, आगे ऐसा नहीं होगा । आज अहंकार भाव नहीं है । हमने विनम्रता प्रकट की है सेवा के रूप में। हमने समाज के प्रति गहरा लगाव प्रकट किया है—जैसा लगाव, जैसा भक्त का भगवान के प्रति, मां का संतान के प्रति । उसी प्रकार का भाव ले कर हम ने अपने कर्त्तव्यों का पालन करने की कोशिश की है ।

गरीबी, भुखमरी और बेकारी आदि सभी समस्याओं के सम्बन्ध में हम ने विचार किया है । विदेशी धन के माध्यम से अर्थ-प्रधान आयोजन के कारण, केन्द्रित अर्थ-प्रधान व्यवस्था के कारण, हमारे देश में बेशुमार समस्यायें पैदा हुई । गरीबी, बेकारी, भुखमरी, उजड़ते गांव, बिगड़ते शहर, जगह-जगह ला एंड आर्डर की प्राबलम, हाउसिंग की प्राबलम, ये सब बातें उस प्रकार के विकृत चिन्तन का दुष्परिणाम हैं, या उसके लाजिकल कानक्लूजन्ज हैं, जिसको ले कर हम पहले चलते रहे हैं ।

जनता पार्टी ने इस चिन्तन को आमूल-चूल बदलने की कोशिश की है । उसने नये योजना आयोग का गठन किया है । उसने नये प्रकार से प्लानिंग किया है । विकेन्द्रित ढंग की ओर गांव-प्रधान योजना और श्रम-प्रधान योजना के द्वारा हम ने एक नये प्रकार की अर्थ-व्यवस्था स्थापित कर के समाज और जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए एक नई दृष्टि पर विचार किया है । उसी दृष्टि के अनुसार राष्ट्रीय विकास योजनाओं की शुरूआत की गई है । आज हमने गांवों को प्रधानता दी है, क्योंकि हम मान कर चलते हैं कि गांव का विकास भारत का विकास है । भारत क्या है ? गांव है । गांव ही भारत है, यह हमारी मान्यता है । हम मान कर चलते हैं कि गांव ही भारत की भाग्य-लक्ष्मी का केन्द्र है, गांव ही वास्तव में भारत की भाग्य-लक्ष्मी का मंदिर है । पहनने का कपड़ा, खाने का अनाज, देश की जनशक्ति, मशीन का पहिया चलाने वाला मजदूर, सीमा की सुरक्षा का जवान, इस देश की, खेत का पानी, भू-शक्ति, जल-शक्ति, हर तरह की शक्ति और भारत की पूर्ण प्रतिभा का केन्द्र ग्राम है । लेकिन ग्राम आज तक ओझल होता रहा । हम ने उस ग्राम को प्रधानता दी और इस दृष्टि से उस ग्राम की योजनाओं का जब विचार किया गया और उन को लागू किया गया तो दो वर्ष से थोड़े ही समय के अंदर वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रौढ़ महिलाओं के लिए घरेलू धन्धों की कल्पना, पंचायती राज का शुभारंभ और इस के अतिरिक्त भूमि सुधार की योजनाएं, इन सारी चीजों की, गांव का विचार कर के हम ने शुरूआत की और आप आश्चर्य करेंगे कि हम ने साढ़े छः लाख हेक्टेयर भूमि उन भूमिहीनों के अंदर वितरित की है जो गांवों में बैठे सिसकते थे, जो रोटी के लिए भी रोते थे । यह पहली बार हम ने किया है और यह इस देश की स्थिति में एक चमत्कारी उपलब्धि है, दुनिया के इतिहास की दृष्टि से एक उपलब्धि है कि 26 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की क्षमता हम ने एक वर्ष के अन्दर तैयार की । यह संसार के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है । क्योंकि गांव का हम ने विचार किया, क्योंकि हम ने अपने कर्त्तव्य के केन्द्र की पूरे तौर पर एक बार पहचान कर ली, इस के कारण हम यह कर पाए ।

इस संबंध में मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम ने जो इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं लागू की हैं, प्लानिंग कमीशन के कहने से या मैं समझता हूं कि प्रान्तों को भी साथ ले कर के जो कुछ योजनाएं बनी हैं, उन के ब्यौरे में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन माननीय सदस्यों से मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि गांव के गरीब किसान, हरिजन, गिरिजन तथा गांव के पिछड़े वर्गों और पिछड़ी जातियों के लिए, सभी के लिए उन योजनाओं के अंदर पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है इस सरकार के खजाने से । लेकिन सरकार तो आज लोकतंत्रीय पद्धति के अंदर एक राजा का महल नहीं कहलाती। लोकतंत्रीय पद्धति के अंदर सरकार समाज के अंदर बिखरा हुआ एक बहुत बड़ा परिवार है । इस दृष्टि से इस खजाने से लाभ कैसे उठाया जाय ? मैं अपने तौर से सोचता हूं, हम ने पंचायती राज की व्यवस्था की है । पंचायत से ले कर संसद् तक के अधिकारों को विकेन्द्रित करने की दृष्टि से विकेन्द्रित व्यवस्था के अंदर राजनैतिक सत्ता को भी यहां केन्द्रित करने की हम से कोशिश नहीं की, उस को भी एक विकेन्द्रित व्यवस्था के अंदर ले गए हैं । ऐसी अवस्था में अगर संसद् सदस्य अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे कि कैसे गरीब आदमी को इस खजाने से पैसा दिलवाया जाय, कैसे उस के लिए एक यंत्र खड़ा किया जाय तब तक काम नहीं चलेगा । सरकार ने मंत्र दिया है, सरकार ने तंत्र दिया है लेकिन यंत्र हमें मिल कर के खड़ा करना पड़ेगा । उस यंत्र की दृष्टि से

[श्री यशदत शर्मा]

पंचायत के लोगों से लेकर के पंचायत समिति के लोग, फिर ब्लाक समिति के लोग, फिर विधान सभा के लोग और फिर हम संसद् सदस्य, हम सब मिल कर एक परिवार हैं । हम दलों की दृष्टि से एक दूसरे से दूर दूर हो सकते हैं लेकिन देश की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, उसकी सेवा की दृष्टि से हम एक परिवार के अंग हैं । इस दृष्टि से लोक सभा के क्षेत्र के स्तर पर भी अगर ऐसी एक टीम न बनाई गई जो टीम इस प्रकार की सम्पूर्ण योजनाओं को गरीब किसानों के हित में उपयोग में ला सके और इस बात को देख सके कि उसे कैसे सरकारी खजाने से ला कर कुछ दिया जाय, तब तक यह काम होने वाला नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में जानकार और ईमानदार इन दो शब्दों का प्रयोग करता हूं तो बड़ी सजगता के साथ प्रयोग करता हूं । मैं जानबूझ कर के इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं । पिछले तीस वर्षों के अंदर सरकार ने कोई ऐसी आयोजना नहीं की, पिछले तीस वर्षों में सरकार ने गांवों के लिए या गरीबों के लिए कुछ धन की योजना अपने बजट में नहीं की, ऐसी बात नहीं है । अवश्य की । परन्तु उसके अंदर मुश्किल क्या थी कि ऐसे जानकार और ईमानदार लोग उस यंत्र में नहीं खड़े हो सके जो उस तंत्र को समझ लें कि कैसे प्राप्त करना है और ईमानदारी से जिसके लिए जो सरकार के खजाने से प्राप्त किया उस को उसके झोंपड़े तक कैसे ले जायं । जानकार व तो ईमानदार नहीं थे और ईमानदार थे तो जानकार नहीं थे । इसलिए मैं यह विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि ईमानदार और जानकार लोगों का हम एक तंत्र खड़ा करे जिस तंत्र से इन योजनाओं को कार्यान्वित करना संभव होगा । अगर हम संसद् सदस्य एक साल बाद फिर आकर के इसी बात के लिए कहना शुरू करते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला तो उस गरीब आदमी को तो कुछ नहीं पता जो अस्पताल में डाक्टर से दवाई लेना नहीं जानता, जो अपनी तारीख भुगतने के लिए जिसे पैसे देकर वकील करता है, उस वकील के दरवाजे में घुसने की क्षमता नहीं रखता, वह बेचारा इस खजाने से पैसा कैसे प्राप्त करेगा ? इसके लिए हमें तंत्र खड़ा करना पड़ेगा । इसलिए मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस स्थिति पर हमारे माननीय सदस्य अवश्य विचार करें । केवल दलों की दृष्टि से इसके ऊपर सोचने से बात नहीं होगी ।

एक बात मैं ने कही कि किसानों के विकास का जब हमने विचार किया तो किसान की सम्पन्नता को देश की शक्ति माना । यह केवल कथनी में ही नहीं, हमने इसको करके भी दिखाया । उसके परिणाम भी प्राप्त हुए, चमत्कारिक परिणाम । जहां तक अन्न के उत्पादन का सवाल है, 1977 से पूर्व लगातार खाद्यान्नों का अभाव हमारे लिए एक रिहता आ छाव रहा है । पहले जब कभी इस सदन में यह सवाल आता था तो माननीय सदस्यों को कभी बाढ़ की बात बता दी जाती थी और कभी सूखे का संगीत सुनाया जाता था लेकिन राहत का कोई रास्ता नहीं दिखाया जाता था । लेकिन मैं समझता हूं हमारी सरकार ने किसानों का विचार करके पहली बार इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाए । गत वर्ष इस देश में अभूतपूर्व बाढ़ आई । समुद्र तट के प्रदेशों में दिल दहलाने वाले सागरीय तूफान आये । उससे पीड़ित परिवारों, हुतात्माओं के लिए मैं गहरी सहानुभूति एवं संवेदना प्रकट करता हूं । इतनी भयंकर बाढ़ आई जिसमें हिमाचल से लेकर सुदूरपूर्व बंगाल तक सारा देश जलप्लावित हो गया लेकिन फिर भी हमारा अन्न का उत्पादन पिछली सारी सीमाओं को लांघ गया फिर चाहे वह गेहूं हो या धान हो । इस प्रकार से बाढ़ का भी एक रिकार्ड रहा और अन्न उत्पादन का भी रिकार्ड रहा । इसका कारण यही है कि हमारी योजनायें ठीक थीं और वह ठीक प्रकार से चल रही थीं । हमारी सरकार ने 26 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था एक ही वर्ष में कर दी थी । किसानों को उर्वरक प्राप्त करने की सुविधायें पूर्णरूप से प्रदान कर दी गई थीं । इसके अतिरिक्त कोआपरेटिव रेजोल्यूशन करके सहकारी संस्थायें बना दी गई थीं । सभी प्रकार की सुविधायें किसानों को प्रदान करा दी गई थीं और इसी कारण किसानों की क्षमता का दोहन हो पाया । आजतक किसानों की शक्ति का दोहन नहीं हुआ इसीलिए वे पीड़ित रहे । जब हमारी सरकार ने किसानों की शक्ति का पूरी तरह से विचार किया तो दो वर्ष में ही हमें उसके सुफल प्राप्त हुए ।

म कहना चाहूंगा कि यह महान् सेवा कार्य हमने समाज के सहयोग से किया है, देश की दृष्टि से परिवार की भावना से किया है । जब मैं परिवार भावना की बात करता हूं तो उससे मेरा मतलब यह है कि प्रान्तों और केन्द्रों के बीच पहले लगातार तनाव चलते रहे । कारण यह कि छोटे बड़े का भाव रहता था और अपना न मान कर चलते थे । दरियाओं के पानी पर लगातार झगड़े चलते रहे । जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार शुरुआत की कि प्रान्तों तथा केन्द्र के बीच दुराव नहीं रहेगा । प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन वे एक शरीर हैं । इस प्रकार से हमने विचार किया और उनको परिवार का अंग मान कर प्रान्त और केन्द्र एक साथ मिल कर बैठे । वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की थीं तथा नेशनल डेवलपमेण्ट कौंसिल ने जो सिफारिशें की थीं उनको केन्द्र ने तत्काल माना तथा प्रान्तों को जो भी देना था वह दिया । इस देश की सेवा के कार्यों के लिए सभी को मिल कर काम करना है । इसलिए हम सभी को साथ ले कर चले । मैं पंजाब में रहता हूं इसलिए मुझे पता है कि पाकिस्तान के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत रावी के पानी का उपयोग सन् 1971 से आरम्भ कर देना चाहिये था लेकिन वह मामला अधर में लटकता रहा । मैं किसी क

लिए कोई हलका शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता लेकिन भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कभी इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं की कि राजस्थान हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर इकट्ठा बैठ कर बात करें। लेकिन 1977 में हमारे प्रधान मंत्री जी न तीन महीने के बाद ही सभी प्रान्तों से एक साथ बैठ कर बात की और पौन डैम की योजना चालू हो गई। यह सौभाग्य की बात है कि रावी के पानी का उपयोग शुरू हो गया है। इसी प्रकार नर्मदा नदी के पानी के सम्बन्ध में भी वास्तविक विचारविमर्श शुरू हो गया है। अब प्रान्तों में पानी के सम्बन्ध में विवाद नहीं रहे। आज प्रान्तों की योजना की दृष्टि से, आज प्रान्तों के कल्याण की दृष्टि से, मैं यह समझता हूं कि पहली बार यह स्थिति आई है और प्रान्त महसूस करने लगे हैं कि केन्द्र हम से दूर नहीं है, बल्कि हमारे परिवार का अंग है, हमारा बड़ा है, उस के पास जा कर हम अपनी समस्याओं को रखेंगे तो हमें हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे। वे बारबार मिल कर बैठते हैं और इस बात के लिए मैं इस सरकार को साधुवाद देता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि मुद्रा और वित्तीय नीतियों में हमने "अर्थायाम" की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है। जैसे शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता जैसे प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है, उसी तरह से अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए "अर्थायाम" की आवश्यकता है। यह अर्थायाम आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन पहली बार हमारी सरकार ने इसके द्वारा देश की सारी अर्थव्यवस्था को कण्ट्रोल करने और वित्तीय व्यवस्था पर काबू पाने का प्रयास किया है और वह भी किसी डण्डे के द्वारा नहीं, किसी प्रकार की जादूगरी के द्वारा नहीं, केवल वित्तीय और मुद्रा नीतियों के नियोजन और उनके अनुशासन के द्वारा आज पहली बार भारत गर्व के साथ दुनिया में खड़ा हो सकता है, हमने मुद्रास्फिति पर पूर्ण रूप से काबू पाया है और इसको "जीरो प्वाइंट" पर ला कर खड़ा कर दिया है। यह बात केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि वर्ल्ड बैंक ने यह सर्टिफिकेट भारत को दिया है। आज अमरीका के डालर की स्थिति डावांडोल है, ब्रिटेन का पाउण्ड लड़खड़ा रहा है, लेकिन भारत का गोल रुपया "अंगद" की तरह अपना पांव टिकाये खड़ा है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम ने प्रान्तों और केन्द्र के बीच की जोनल दीवारों को तोड़ दिया है और इन जोनल दीवारों को तोड़ कर वितरण व्यवस्था को स्वस्थ और मजबत बना दिया है। आज बम्बई जाते हुए मेरी सुपुत्री को—वह बम्बई में रहती है—यह नहीं कहना पड़ता कि मेरे लिए एक किलो चावल लेते आइयेगा। क्योंकि वह वहां बहुतायत से मिलता है। आज दक्षिण के बन्धुओं को ऐसी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि जोनल दीवारें तोड़ दी गई हैं और वितरण व्यवस्था स्वस्थ हो गई है। आज उपभोक्ताओं का सब जगह अपने आवश्यक पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं और उत्पादकों को अपना माल बेचने के लिए देश के चारों कोने खुले हुए हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह मौलिक नीति है जिसके ऊपर हमने विचार किया है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं —जनसेवा के संस्थानों का भी हमने परिष्कार किया है। मेरे मित्र प्रो० मधु दण्डवते चले गये —उन्होंने अपने नाम के अनुसार ही अपना काम किया है। रेल सेवाओं के अन्दर उन्होंने जो चमत्कार पैदा किया है —ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पिछले तीन वर्ष के बजट पेश करके उन्होंने रेल योजना को बहुत अच्छी तरह से चलाया है। उन्होंने श्रेणी-भेद को—फर्स्ट क्लास, सैकण्ड क्लास, थर्ड क्लास—यानी क्लासिज्म को वहां से समाप्त करने की कोशिश की है और यह कोशिश अभी भी चल रही है, लगातार चल रही है और एक दिन ऐसा आयेगा जब रेलों में केवल एक ही श्रेणी चलेगी और उस के अन्दर पहले दर्जे की वे सब सुविधायें मिलेंगी जो आज उस में मिल रही हैं। रेल सेवाओं में यात्रियों की सुविधायें और रेल कर्मचारियों की सहायता की दृष्टि से वे मधु के समान मीठे हैं लेकिन वहां की इन-एफिसियेन्सी और वहां के मिस-मैनेजमेण्ट के ऊपर वे दण्ड के समान पड़ते हैं। ऐसे मधु दण्डवते को मैं बधाई देता हूं। यह वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने पहली बार इस देश के अन्दर—शायद दुनिया की किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री ने अपने बजट में इस "बाल वर्ग" का इतना सत्कार नहीं किया होगा, जितना मधु दण्डवते जी ने किया है। इन सब बातों के साथ-साथ वह इस समय यहां नहीं हैं, वरना मैं उनसे इस समय कुछ पंजाब की बातें भी करता।

अब मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। विदेश नीति के बारे में यहां और राज्य सभा के बारे में भी मैंने समाचार पत्रों में कुछ चर्चा पढ़ी है। माननीय अटल की बहुत सक्षम हैं, वह स्वयं उन बातों का उत्तर दे सकते हैं। चीन की यात्रा को लेकर कुछ चर्चायें खड़ी हुई हैं। मैं आज भारत के विदेश मंत्री के ऊपर गर्व कर सकता हूं कि जो प्रधान मंत्री जी का दायां बाजू बन कर उन की नीतियों और सन्देश को विश्व में फैलाने की दृष्टि से अपनी वाणी द्वारा अपने मस्तिष्क और अपनी प्रतिभा का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वह चीन क्यों गये, जब चीन का आक्रमण हो रहा था।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जाने से पहले हवाई-अड्डे पर अपना बयान दिया था कि मैं कोई टोस सुझाव ले कर नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं केवल टटोलने के लिए जा रहा हूं और जितना समय टटोलने के लिए था, उस के एक दिन पहले ही टटोल कर आ गए और टटोल कर नंगा कर के दुनिया के सामने खड़ा

[श्री यज्ञदत्त शर्मा]

कर दिया । इस नाते मैं यह कहना चाहूंगा कि हम ने कुछ गंवाया नहीं है । पंचशील की बात हुई है । हम अपनी बात कहने से क्यों रुकेंगे । पंचशील की बात कहना कोई पाप नहीं है । मैं उस महान नेता के ऊपर बड़ा गर्व कर सकता हूं, जिन के नाम के आगे आज दुःख से स्वर्गीय लगाना पड़ता है । 1954 की 26 अप्रैल को माननीय जवाहरलाल नेहरू ने भी पंचशील की बात कही थी । इस के अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि साधु की कहने की बात अपनी रहती है लेकिन खल क समझने की बात अपनी रहती है । जब मैं अपने देश के साधवाद का विचार करता हूं, तो कौन मेरी बात को कैसे समझता है, उस का मैं विचार नहीं करता । इस नाते मैं यह कहना चाहूंगा कि आज अफ्रीका के उन देशों क प्रति, जो अपने आप को दलित महसूस करते हैं, हमारी विदेश नीति क्या है । हम ने न कवल हिन्द महासागर क्षेत्र को शान्ति क्षेत्र कहने की बात कही है बल्कि दूसरे क्षेत्रों को भी शान्ति का क्षेत्र बनाने की बात कही है । आज दुनिया के बहुत से देश और खास तौर से दक्षिण-पूर्वी देश हमारे साथ इस बात में एक हैं कि न केवल हिन्द महासागर क क्षेत्र को बल्कि पूर्ण पूर्वी क्षेत्र को शान्ति का क्षेत्र बनाया जाए और इस के साथ भूमि भी जुड़ गई है । इस दृष्टि से आज विश्व के एक-चौथाई क्षेत्र को शान्ति का क्षेत्र बनाया जाए और मेरा विश्वास है कि हम समय पाकर सम्पूर्ण विश्व को शान्ति का क्षेत्र बनाएंगे । यह हमारी विदेश नीति का एक बहुत बड़ा पहलू है ।

इस सम्बन्ध में म एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । हम सब की भलाई क लिए काम कर रहे हैं और हमारा अपना प्रयास देश की जनता का भला करना है लेकिन म जानता हूं कि हमारा एक करोनिक नेशेंट से वास्ता है । इस देश का जो रोग है, वह बहुत पुराना और जीर्ण रोग है । इसलिए हम ने रोगी को वद्य और अपनी ईमानदारी के प्रति विश्वास दिला दिया था । पूण निरोगिता हो, यह समय की बात है और यह हो कर रहेगी, इस का मुझे विश्वास है लेकिन आप के माध्यम से मैं बड़े दुःख के साथ और भारी दिल के साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा:

अजब तासीर है मेरे महबूब की ।

मैं कुश्ता भी बस जाऊं तो उन्हें मुआफिक नहीं आता ।

वे फिर भी आलोचना कर रहे हैं, फिर भी हमें गाली दे रहे हैं और कहते हैं "देयर इजनो डाइरेक्शन", इन की कोई डाइरेक्शन नहीं है । मैं समझ नहीं पा रहा हूं । डाइरेक्शन क्या होती है ? क्या डाइरेक्शन वह होती है जो 25 जून, 1975 से 1977 तक देश की जनता को दिखाई गई ? क्या डाइरेक्शन वह थी जो 19 दिसम्बर, 1978 के बाद बस देश की जनता को दिखाई गई ? क्या डाइरेक्शन वह थी जिस से पथभ्रष्ट जवानी हवाई-जहाज को ले उड़ी ? क्या डाइरेक्शन वह थी, जिस से पथभ्रष्ट हो कर जवानी बसों के अन्दर जिन्दा यात्रियों को जला बैठी ? मैं उन जवानों को दोष नहीं देना चाहता बल्कि मैं उन डाइरेक्टरों को दोष देता हूं जो इस पाप के पापी हैं । मुझे इस बात का दुःख है ।

अन्त में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमें दिशा देने की जरूरत नहीं है । तुम ने जो दिशा दी, उसे देश की जनता ने देख लिया, उस के कुफल देश की जनता ने भोग लिये, उस का देश की जनता अच्छी तरह से विचार कर चुकी है । हमें दिशा दिखाने की जरूरत नहीं है । अब तुम अपनी बैलेंसशीट सुधारने की कोशिश करो, अपनी बैलेंसशीट संवारने की कोशिश करो क्योंकि अपनी बैलेंसशीट संवारने के बाद ही तुम्हें देश के अन्दर कोई स्थान मिलेगा हमें दिशा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है । मैं माननीय स्टीफन साहब की नीयत पर कोई शक नहीं कर रहा हूं । नीयत पर शक करूं तो लोकतंत्र की मर्यादा गंवा बैठूं । मैं उनके प्रति प्यार रखता हूं । आई लव हिम, मैं अंग्रेजी में बताता हूं । मैं उन के प्रति प्यार रखता हूं । मैं उन की नीयत पर शक नहीं करता । मुझे लगता है कि वे गाली इसलिए देते हैं कि इस अच्छी सरकार को कहीं उनकी बद नजर न लग जाए ।

बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

SHRI ASOKE KRISHNA DUTT (Dum Dum): Mr. Speaker, Sir, I stand here to second the motion that has just now been very ably moved by my friend, Pandit Yagya Dutt Sharma, thanking the President of our country for the memorable Address that was delivered on the 19th of this month.

Sir, within the limited time that has been allotted to me, I shall try to confine myself to those aspects of the President's Address which have not been covered at length by my friend. It is very significant that the President began his Address by referring to the devastating floods that wrought tremendous havoc in our country during the last year. Many of us on both sides of the House who have had the occasion to visit the devastated areas have been what a tremendous havoc these flood had caused. Possibly in recent history we have never heard of such tremendous devastation. The President has enumerated the tremendous loss that we have suffered and at the same time he had very significantly mentioned about the manner in which various sections of the country stood up to meet the challenge of nature. He has rightly praised the various agencies and individuals who did yeoman service for re-construction. The role of the defence forces and the police personnel have very rightly been praised because they

worked round the clock and they definitely worked beyond the call of duty. Sir, wih the concerted effort we can surely overcome the great devastation that has come upon us.

Mr. Speaker, Sir, the Address of the President reflects the thinking of the Government which enjoys the confidence of this House. Sir, when this government came in power two years ago it came with the mandate from the people—a mandate for a change and also a mandate for re-construction. The people of this country voted this government to power with the mandate calling upon the government to banish two of the greatest evils that can come upon mankind-tyranny and poverty.

Sir, we on this side of the House who support the government went to the samadhi of Mahatma Gandhi before the government took office. On that memorable day all of us took the pledge at Rajghat to banish tyranny and poverty. This government after coming into power took upon the task of undoing the great wrongs and evils that were done in the name of Emergency. During the Emergency our fundamental rights were curtailed, Press was gagged. the mass media-completely owned and controlled by the State, that is, television and radio—were managed in such a way that instead of serving the nation and serving the people they became organs for serving a coteric of individuals headed by an ambitious individual who tried to create a dynasty. This government has undone those wrongs. The constitution was tampered with. The Constitution has now been restored to its old glory. These are matters for which the government can rightly be proud of.

MR. SPEAKER: The hon'ble Member will continue his speech after lunch.

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled, after lunch, at six minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI RAM MURTY *in the Ctair*]

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENTS' ADDRESS—Contd.

MR. CHAIRMAN: Mr. Dutt will now continue his speech.

SHRI ASHOKE KRISHNA DUTT: When the House adjourned for lunch, I was talking about the attempt to control the mass media—television and radio—made by certain interested persons. Very significantly, the President's Address has enumerated several provisions in the electoral reform, and talked about the changes that are going to be brought about in the control and management of Akashvani and Doordarshan. These are very significant; and we take it that in future, no such designing person, whoever he or she might be, well ever attempt to misuse high office and commit excess.

The manifesto of the present ruling party had clearly said that power, both political and economic, would be devolved. My friend, the mover of the resolution, has discussed in detail about the shift of the centre of gravity of power from urban to rural areas. I will not repeat them, but the one aspect which I would like to mention is that many friends, particularly in States often say that States do not get their proper share. We can proudly recall that the present, i.e. the 6th Five-Year Plan has programmed an out lay where the investment in the State sector is for the first time higher than the investment in the Central sector. This is a very significant change.

The President's Address has spoken about the agricultural and industrial development of the country.

For the first time we have had a record food production of 125.6 million tonnes and inspite of the great obstacles caused and natural calamities, the industrial production has also

(Shri Ashoke Krishna Dutt.)

shown a record figure. The national income of the country in 1977-78 has grown by 7.4 per cent as against 1.4 per cent the year before. This is a remarkable achievement by itself. But we cannot fully realise the significance of this unless we compare the figures of other developing and devoloped countries. For instance, let us take our immediate neighbour Pakistan. The annual average growth rate for the last 15 years in Pakistan was 3.3 per cent of that in the last five years it was only 0.8 per cent. Japan is considered to be one of the most economically advanced countries in the world and undoubtedly the most advanced in Asia; in fifteen years the average economic growth rate was 7.7 per cent annualy. But if we take the annual average of the last five years of those 15 years it has been only four per cent. If we compare it with other countries, say, Sri Lanka and Bangla Desh, what do we see? They may be small countries in size or population but their problems, both economic and human, are similar to ours. During the last five years Bangla Desh had a negative growth rate, minus 2.3 per cent Shri Lanka had 1.1 per cent. Against them our achievement in the last year is remarkable.

I should like to remind some of my friends who believe that though the Emergency curtailed our rights and affected us badly, it helped us in economic growth: they said that the discipline that was there during the emergency was helpful. The figures I have quoted show how wrong they are. During the last year of the Emergency inspite of all that regimentation and tyranny and discipline, the growth rate was 1.4 per cent. It has now been shown that through the democratic processes a free people toiling for the development of their country can show results which are far more remarkable than any regimented regime can achieve; the figure are clear. This tremendous amount of growth has helped us in maintaining the price line... (An Hon. Member: What about China?) China has consistently maintained a growth rate of 5 per cent; it was 5 per cent last year as against 7.4 per cent in our country. As I said it has enabled us to maintain the wholesale price index variation between two per cent. If we compare with Pakistan it varies between 5 and 6 per cent. Australia is a very advanced country in this area; it has also a tremendous growth rate; there the price variation is about ten per cent. In our country it was kept within two per cent. These are remarkable achievements and it is oppropriate that the President has mentioned them.

The President's Address mentions about the massive national adult education programme. When our country came out of the shackles of imperialism, the literacy rate was only 3 per cent. In the last 30 years it has improved and reached about 30 per cent. It has definitely improved but it is nowhere where we expected it to be. This programme is not an over-ambitious programme. It says that within a decade this massive programme will completely eradicate illiteracy from this country. I think it is very significant that the Education Minister came in when this point was being talked about.

This is the International Year of the Child and very significantly the President has also mentioned about it. But while giving vent to the rural bias the tremendous amount of agricultural development, adult education and other social matters, the President's Address has not overlooked the necessity for scientific and technological development. For the first time, a tremendous amount of money is being spent. What was spent during the fifth plan was much higher than the earlier plans. But the sixth plan envisages an expenditure which is even double what was spent in the fifth plan for scientific and technological development.

The President's Address very rightly deals at great length with our foreign policy. Different aspects of the

foreign policy have been discussed like our relationship with the Arab countries in West Asia, the role that India has been playing in combating racialism in Africa, our relationship with the South-East Asian nations and with Japan. But particular emphasis has been given to our relationship with the super powers. So far as America is concerned, we are very happy that our relations with that country are much better today. The last regime went out of its way to be unfriendly with the United States. We have had serious differences with that country over Kashmir, Bangaldesh etc. but we should also remember that often in times of serious national crisis, the United States has stood by our side like when the Chinese invaded us last time. So, there is no reason why we should be unfrientdly with them. This Government has tried to bring back the old friendly relationship. But what is more significant is our relationship with the Soviet Union. This Government has established for better friendship with the Soviet Union than the last regime did. Some of my friends may be critical about it. They might think that there was a much closer understanding with the Soviet Union during the last regime, but I am not one of those who believe that. During the last regime, we did not have proper friendship with the Soviet Union. Those who think we did equate subservience with friendliness. Friendship must be on equal footing. There must be mutual respect. During the last regime the mutuality of respect was missing.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): He used the word 'subservience'. We were never subservient to anybody. If he says like that, I would say that the Janata Party is subservient to America.

SHRI ASHOKE KRISHNA DUTT: I do not believe in subservience. I am not saying anything derogatory to our country. I am proud of my country. I am proud that the whole world respects my country far more today than when my country was suffering under the shackles put by people who were trying to curb democracy and kill fundamental rights. The friendly attitude of the Soviet Union, the respect that they now have for us, is clearly evident from the fact that our Prime Minister was given one of the finest and grandest reception last year when he visited the Soviet Union. We are trying to be friendly with China. Many friends may not like it; some have cynically remarked about what is the necessity of our going out of our way to befriend China? I feel there is every reason for us to befriend China, because we are both ancient civilisations, having contacts for over thousands of years, because our economic problems are very similar. We both have a huge population; they are 850 milion and we are 650 million; added together, we constitute more than half the people of the world. In this background, we must remember that the unfriendly attitude between India and China for the last several years have over-burdened both of us with unnecessary expenditure on modern military weapons. We cannot afford that. It was very proper that friendliness was attempted. May be we have taken one step further than what was needed, but when the interest, enlightened self-interest of hundreds of millions of people are concerned, we should not stand on pride and vanity. We attempted to befriend China, but we had a set back. While our Foreign Minister was still in China, they invaded the friendly nation of Viet Nam in a manner which reminds us of what happened in 1962. It is a set back, but we will try to overcome that set back.

I thought the Chinese ought to remember that though Viet Nam is much smaller in size than China, though its population may be much less than that of the Chinese population, China should not forget that in courage and determination ,the Vietnamese are not small. One of the most powerful, if not the most powerful super-power of the world, tried

(Shri Ashoke Krishna Dutt.)

to curb Viet Nam for several years militarly with the most sophisticated and most brutal and cruel weapons, but the Vietnamese stood up to that. They will show it again and the present Chinese aggressors will have to go back. It is very unfortunate that the Chinese are not realising the situation, as they should. I think the Vietnamese will teach them that lesson, and the Chinese will have a proper perspective.

The Presidential Address also mentions another very significant aspect about external affairs. We found that many of the highly developed countries of the world, particularly of the European Economic Community, who for years pretended to be the patrons trying to help us in our economic development, recently launched on a programme of protectionism, which is definitely damaging the growth of not only India but of all developing countries in South East Asia and Africa. Our Government have taken a lead in raising this issue in international conferences so that a tremendous public opinion has been created, and now the developed countries are re-thinking about their policy of protectionsm.

The President's Address mentions about defence preparedness almost at the end. Though it comes last, it is not the least. I was here two days ago when the Deputy Prime Minister and Defence Minister in reply to a question clearly reminded the House that the India of 1979 is not the India of 1962. Just after the debacle of 1962 I had been to many of the South East Asian countries and I had seen the amount of contempt that the people of those countries had for India. Again, very recently I visited those countries hardly a month ago, and I found that everywhere Indian foreign policy and Indian defence preparedness is being viewed with a new respect. We do not like to spend a tremendous amount on defence expenditure. In a developing country like ours, suffering under poverty, where 70 per cent of the people are still below the subsistence level, thanks to the last 7 or 8 years of misrule and two years of emergency, it is very difficult for us to spend a large amount on defence.

Some of my friends in their exuberence talk about nuclear development, talk about sophisticated weapons, but if we just calculate the tremendous cost that modern weaponry involves, we shudder to think what will happen to national development if we spend so much on this unproductive expenditure. But in spite of that, we have got to be prepared, we always hope for the best, but we must remain prepared for the worst that nothing like 1962 happens again and that preparedness is there.

I have toured throughout the length breadth of the country in the last two years seen many of the Defence establishments and everywhere the morale of the Army has reached new heights. Our Army today has the finest discipline and finest morale and our preparedness is there. We are manufacturing sophisticated weapons ourselves and we are also importing necessary weapons which we cannot manufacture here, with such a programme that within the immediate future we will be able to manufacture those things ourselves.

Sir, I think my time is coming to an end. Before I conclude, I appeal to all section of the House to remember that we are standing at the cross-roads of history. Our nation which has re-established democracy and is now fighting the greatest evil of poverty has got to stand united. We have got to make a concerted effort, a great effort, and great efforts are never easy. We have tremendous amount of hard work before us and that can be successful only if we combine together.

The President has fervently appealed to a spirit of united national endeavour. Sir, I believe he has echoed

the thousands of years old sayings of the Upanishads :

समानो मंत्र: समिति: समानी
समानं मन: सह चित्तमेषाम्

Sir, with these words I commend the motion to the House and I appeal to all sections of the House to unanimously adopt the motion that has been so ably moved by my friend just before me.

MR. CHAIRMAN: Motion moved :

"That an Address be presented to the President in the following terms:—

'That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 19th February, 1979.'"

Hon. Members may now move their amendments.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address about the efforts being made by the Government to mobilise opinion in various countries about the establishment of a World Constituent Assembly for drafting a Constitution for the 'Federation of Earth' of a World Government." (1)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that in pursuit of our foreign policy of improving relations with our neighbours, no mention has been made in the Address about our normalising relations with China by suggesting a formula that China recognises the McMahon line in the Eastern sector and accepts the *de jure* sovereignty of India over Aksaichin while India gives a ninety-nine years' lease of Aksaichin territory to China like China's lease of Hongkong to the British." (2)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address has failed to condemn the virus of casteism and hatred being injected into the body politic of the nation by actions and utterances of leaders of various parties in recent months thereby striking at the root of Indian nationhood and shattering the very basis of formation of a classless and casteless society." (3)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address to remove the various regional imbalances so far as development is concerned in the Sixth Five Year Plan and of giving a raw deal to Orissa by not including it in the special category of States for Central plan assistance." (4)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address about the need for registration of political parties under the Societies Registration Act, 1860 and publication of their annual accounts duly audited by a Chartered Accountant." (5)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address about the date line by which the Lokpal and Lokayukta Bill will be passed and the institutions of Lokpal and Lokayukta will start functioning to look into the grievances and complaints of private individuals." (6)

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the prevention of Harijans, Girijans and other weaker sections in exercising their vote freely."(7)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the growing number of atrocities prepetrated on Harijans and Girijans and the failure of the Government to prevent them."(8)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to keep the prices of cash crops at remunerative level."(9)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the need for conversion of Katpadi—Tirupati metre gauge into broad gauge." (10)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that in the Address no concrete measures have been spelt out for solving the problem of unemployment."(11)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the need to delink the newspapers from the big industrial houses."(12)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address about the failure of the Government to reduce the monopoly of a group of families over industrial houses." (12).

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the increase in the cement prices and its scarcity." (14)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Drought Prone Areas programmes which was intended to develop such areas has been disbanded."(15).

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no reference in the Address regarding the inadequacy of foodgrains distributed under Food for Work scheme and for not converting this scheme into Food for Full Employment to wipe out unemployment in the rural areas thereby increasing the purchasing power of the rural poor and to effect integrate rural development".(16)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address about the Reserve Bank restricting the cooperative societies not to issue loans to those who are not having any debt in the societies and to the new members if the societies are having more than 25 per cent of overdues and the difficulties caused by this policy." (17)

That at the end of the motion, the following beadded, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address about the failure of the Government to supply essential commodities at reasonable rates in the rural areas." (18)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Addres that the Harijans, Girijans and other weaker sections are prevented from exercising their right of vote." (92)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government in preventing atrocities perpetrated on Harijans by upper classes." (93)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the failure of the Government in formulating uniform policy for giving loans to the rural areas by the Nationalised Banks and allocating at least 40 per cent of the finances of the Nationalised Banks to the rural areas."(94)

That at the end of the motion, the following be added. namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the failure of the Government in creating machinery and necessary funds to give remunerative prices to agricultural commodities."(95)

That at the end of the motion. the following be added, namely:--

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the failure of the Government in reducing the interest rates on the loans given to the agriculturists."(96)

That at the end of the motion, the following be added; namely :

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the failure of the Government to keep down the prices of steel and cement."(97)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no reference has been made in the Address regarding the failure of the Government in protecting the handloom weavers."(98)

That at the end of the motion, the following be added namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the failure of the Government in implementing family planning programme successfully."(99)

That at the end of the motion, the following be added namely:—

"but regarl that no mention has been made in the Address about discouragement being caused to the scientists and technologists in the country."(100)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the tilt of genuine non-alignment policy into alignment policy in foreign affairs."(101)

That at the end of the motion, the following be aded, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the failure of the Government in adopting the policy of self reliance."(102)

[Shri P. Rajagopal Naidu]

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the failure of the Government in modernising the defence equipment." (103)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the chaotic conditions prevailing in the universities and the steps to be taken to set right the affairs." (104)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for establishment in the first instance of a National Insurance Fund against the vast damages caused by periodical, natural calamities like hailstorms, storms, floods, droughts, conflagrations, which create the problems of compensating the peasants and workers for the loss of their crops, homes and means of living and rehabilitating their social economy especially in rural areas." (238).

That at the end of the motion, the following be aded, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the growing disparity in the economic condition of the rural and urban people and Government's failure to alleviate or moderates the crash in agricultural prices." (239)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the establishment of Agricultural Development Bank to finance development activities in agriculture." (240).

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no reference has been made in the Address regarding the murders of Congress (I) workers and leaders and victimisation of persons belonging to Congress (I)." (391)

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret the absence from the Address of clear and concrete steps to be taken by the Government in effectively rooting out corruption which continues to corrode the life and progress of the community and the country." (19)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about continued heavy wasteful expenditure in several governmental departments and agencies, and about the positive measures to be urgently taken to reduce such expenditure." (20)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not contain an specific reference to the alarming situation of constant physical assaults on, and injuries and insults of all sorts being inflicted upon, the Harijans, Girijans and other economically weaker sections of the community." (21)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no reference whatsoever to the near chaotic conditions including closures of several university campuses and academic institutions in different parts of the country." (22)

That at the end of the motion, following be added, namely:

"but regret that there is no sufficient emphasis in the Address on the cruical and urgent need of electroal reforms with a view to ensuring free and fair elections as well as eliminating the evil of money power in our electroral and political processes and practices." (23)

That at the end of the motion, the following be aded, namely:—

"but regret that the Address does not contain a clear, bold and pragmatic policy of development on the economic and industrial fronts in the country." (24)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address takes no notice of recurrence of authoritarian trends in the country and gives no definite indication of governmental and national endeavours for combating them energetically, quickly and purposefully so as to keep in tact and enhance the democratic fabric of the polity." (25).

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the nation's anxiety about brain drain and the steps taken by the Government to stop this phenomenon, speicially the emigration of brilliant and youthful scientists, because of dismantling of the Council of Scientific and Industrial Reserach, and because of lack of coordination between different scientific and research institutions in the country, and also beacuse of wasteful overlapping of scientific efforts in the country." (176)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not include in the Government's Legislative Programme the Adoption Bill, which has been kept in abeyance for nearly 24 years now, though the United Nations Declaration on Human Rights declares the right to a family as a fundamental right, and that 1979, moreover, is the International Year of the Child." (177).

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not contain a clear and firm policy of the Government regarding nationalisation of industries." (178).

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention the much-needed review of about 5000 Collaboration Agreements between Indian and foreign firms in the country." (179)

That at the end of the motion, the folliwing be added, namely:—

"but regret that the Address does not give the Government's plan and strategy to protect and exploit the 200 miles economic and exclusive zone of the Indian seas." (180)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address fails to point out the necessity for a self-imposed ban on the expression of personal views and opinion in public by prominent leaders in office, especially on delicate international and national issues, which has led to some kind of corrosion of the nation's image abroad and also to the loss of valuable human lives within the country, besides destruction of and damage to public properties, on account of popular demonstration being held from time to time against such public expressions of views and opinions." (181)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not give a definitive and clear format of Government of India's Nuclear

[Shri P. Rajagopal Naidu]

Policy, in the background of patent violation of the Agreement by the United States in regard to the supply of enriched Uranium." (182)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the concrete steps taken by the Government to avert the deepening crisis in the Rail transportation of basic agricultural inputs like fertilisers, movement of coal to Thermal Plants, Steel Plants, etc., movement of essential commodities like foodgrains, especially when all restrictions have been removed." (183)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address is silent about the worsening congestion at all the Ports of the country, particularly in Bombay, where more than 100 ships are waiting on high seas, for several weeks, which has led to the weakening of faith in the international shipping world about India's capacity to handle imported cargo efficiently and speedily." (184)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to refer to the measures adopted for fair distribution and economic utilisation of electric power within the country in the form of modernising the ramshackle Load Despatch Centres with modern equipment like computers and telemetres, especially when it is claimed by the Government that the electricity generation has gone up by 13 per cent." (185)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address is silent about the setting up of Agricultural Development Bank, and about the concrete and time-bound [illegible] for strengthening that [illegible] the country's economy, sustaining 75 per cent of the population in the form of crop planning, marketing of agricultural products and farm price structures." (186)

श्री केशव राव धोंडगे (नांदेड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा के मामले में 10 लाख मराठी भाषी लोगों के साथ न्याय करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में दलित और पददलित आदिवासियों पर किये जाने वाले अत्याचारों और अन्याय का कोई उल्लेख नहीं है।"

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और भ्रष्टाचार के कारण संसदीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास डगमगा गया है।"

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में विशेषकर नांदेड़ से उदगीर और गेगाखेड से बोधन तक नई रेल लाईन के निर्माण का उल्लेख नहीं है।"

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कई राज्यों के उपेक्षित क्षेत्रों और मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद तथा पूणे में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित की जाये, जैसा कि विधान सभा ने सिफारिश की है।"

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति स्थापित की जाये जो राष्ट्रीय गान में बदलती हुई क्रांतिकारी परिस्थितियों के अनुसार "अधिनायक" और "भाग्यविधाता" आदि शब्दों में परिवर्तन करे और उसके स्थान पर एक नया राष्ट्रगान तैयार करे।"

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये कि, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि वर्ष में एक बार संसद का एक अधिवेशन आन्ध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में किया जाये ताकि [illegible] और सांस्कृतिक एक्य हो और शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो सके

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नव बौद्धों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सुविधाओं के समान सुविधायें देने का कोई उल्लेख नहीं।" (33)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है किअभिभाषण में देश के किसानों को उनके उत्पादन के उचित मूल्य देने का कोई उल्लेख नहीं है और किसानों की इस मांग को जानबूझकर अनदेखा करने से उनमें भारी असंतोष पैदा हुआ है।" (34)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक संबंध विधेयक के विरुद्ध, जो पूंजीपतियों का साथ देने वाला प्रतिगामी विधेयक है, श्रमिक वर्ग में व्याप्त असंतोष का कोई उल्लेख नहीं है। (35)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:— '.

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जात पात, रंगभेद और धर्म के आधार पर व्याप्त विषमताओं को समाप्त करने और इन त्रुटियों से मुक्त समाजवादी समाज की स्थापना करने तथा हिन्दुओं की धार्मिक पुस्तकों में से जात-पात, रंगभेद और धर्म के आधार पर अस्पृश्यता और असमानता को बढ़ावा देने वाली बातों को निकालकर क्रांतिकारी परिवर्तन करके सम्पूर्ण क्रांति लाने का उल्लेख नहीं है।" (36)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे ग्रामीण जीवन और व्यवस्था को आधुनिक बनाने और देश के ग्रामीण पददलितों और उपेक्षित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी क्रांतिकारी और समाजवादी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।" (37)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के युवा वर्ग की सैनिक प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय विकास के लिए उन्हें एकत्र करने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है। (38)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में, संविधान में क्रांतिकारी और सामाजिक परिवर्तन करने तथा कार्य का अधिकार सम्मिलित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (187)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को उकसाये जाने के कारण अलीगढ़ तथा अन्य स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगों का कोई उल्लेख नहीं है।" (188)

कि प्रस्ताव में अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों द्वारा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर दिये गये सुझावों पर सरकार के निर्णय का कोई उल्लेख नहीं है।" (189)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी के लोगों की पूर्ण राज्य सम्बन्धी मांग का कोई उल्लेख नहीं है।" (190)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 23-12-78 को नई दिल्ली में हुई विशाल किसान रैली में उठाई गई न्यायोचित मांगों के बारे में सरकार की नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (191)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाज के दुर्बल वर्गों को सुविधाएं देने के लिए जाति के स्थान पर आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाने सम्बन्धी नीति तैयार करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (192)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी समाप्त करने और रोजगार देने तथा प्रत्येक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु रोजगारी गारंटी योजना के लिए विधान बनाने का कोई उल्लेख नहीं।" (193)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय मजदूर नीति, राष्ट्रीय मूल्य नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय कराधान नीति, राष्ट्रीय सिविल संहिता नीति, एक राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति और राष्ट्रीय नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा नीति बनाने में सरकार की असफलता और उपेक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।" (194)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा धर्म और संस्कृति के नाम पर धर्म-विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के कारण भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न खतरे और उन्हें रोकने में सरकार

[श्री केशव राव धोंडगे]

की असफलता। जिसके कारण देश भर में व्यापक असंतोष है और सरकार पर समाज विरोधी शक्तियों के प्रभाव से विस्फोटक स्थिति होने और उस ओर सरकार की निष्क्रियता का कोई उल्लेख नहीं है।" (195)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाजवादी समाज की स्थापना और समाजवाद के प्रति सरकार का आकर्षण न होने तथा लोगों पर होने वाले अन्याय को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (196)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की उपेक्षा और करोड़ों बच्चों पर उसके विपरीत प्रभाव तथा बच्चों की उपेक्षा कर के वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहन देने और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के कार्यान्वयन में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (197)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को कानूनी सहायता देने और चलते न्यायालय बनाने और अति जटिल एवं महंगी न्याय प्रक्रिया को जिसके कारण गरीबों को न्याय नहीं मिलता, समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (198)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतंत्रता सेनानियों के नाते रिश्तेदारों को वित्तीय सहायता तथा पेंशन देने में सरकार की उपेक्षा और इन स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों पर होने वाले अन्याय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (199)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कार्यालयों सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों तथा सहकारी क्षेत्र आदि में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और सामान्य जीवन से इस बुराई को निकालने में सरकार की असमर्थता का कोई उल्लेख नहीं है।" (200)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई मुनाफाखोरी, अपमिश्रण, चोरबाजारी और सूदखोरी को समाप्त करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (213)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उचित स्थानों पर ग्रामीण विद्यापीठ की स्थापना कर ग्रामीण अशिक्षा को समाप्त करने के लिए शिक्षित युवा शक्ति का उपयोग करने की नीति का उल्लेख नहीं है।" (214)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अणु विस्फोटों और अणुअस्त्रों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में असफलता का उल्लेख नहीं है।" (215)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर सरकार की पूंजीपतियों का पक्ष लेने की नीति तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए जाने की मांग के प्रति उसकी ओर उपेक्षा अपनाए जाने की नीति की निन्दा किए जाने का उल्लेख नहीं है।" (216)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यूनियन सर्विस कमीशन के त्रुटिपूर्ण नियमों के कारण छात्रों, विशेषकर निर्धन और गरीब छात्रों को न्याय दिए जाने के प्रति सरकार की उदासीनता का उल्लेख नहीं है।" (217)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी कम्पनियों के व्यापार और उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तथा उनके द्वारा किए जा रहे शोषण को समाप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (218)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले, डा० बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा प्रताप तथा अन्य महान व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु दिवसों को सार्वजनिक छुट्टी घोषित किए जाने की लोगों की बड़े दिन से की जा रही मांग का कोई उल्लेख नहीं है।" (219)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मिलों द्वारा कई तथा अन्य कृषि उत्पादों की एकाधिकार खरीद से किसानों को होने वाली हानि तथा उनके उत्पादों का उचित मूल्य न दिए जाने तथा किसानों को संरक्षण प्रदान करने के प्रति केन्द्रीय सरकार की घोर उपेक्षा का उल्लेख नहीं है।" (220)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा ग्रामों में पीने का पानी उपलब्ध कराने में उसकी असफलता का उल्लेख नहीं है ।" (221)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण उद्योगीकरण की सरकार की प्रभावहीन नीति का उल्लेख नहीं है ।" (222)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाज में व्याप्त अज्ञानता, अशिक्षा, जातीयता और धार्मिक अन्धविश्वास की बुराइयों को, जो सदियों से हमारे समाज को खा रही हैं तथा जो संविधान और समानता के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं, दूर करने में सरकार की उदासीनता तथा अकर्मण्यता का उल्लेख नहीं है ।" (223)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय सभ्यता के नाम पर देश में व्याप्त अस्पृश्यता, जातीयता, वर्ग भेद आदि की बुराईयों का, जो संयुक्त राष्ट्र-संघ के मानवीय संकल्प के विरुद्ध हैं, उल्लेख नहीं है ।" (224)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 15 अगस्त, 1947 के बाद अवैध तरीके से राजनीतिक, सामाजिक शैक्षिक, धार्मिक, तथा सहकारिता समितियों सम्बन्धी नेताओं द्वारा इकट्ठी की गई चल और अचल सम्पत्तियों की जांच, उन्हें जब्त करने तथा अपराधियों को दण्ड देने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का कोई उल्लेख नहीं है ।" (225)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उपलब्ध धर्म के नाम पर करोड़ों रुपये की चल और अचल सम्पत्ति का प्रबन्ध इस उद्देश्य से कि उसका उपयोग कमजोर वर्गों के उत्थान में किया जा सके, और भगवान के नाम पर इस लूट को रोका जा सके, अपने हाथ में लिए जाने का उल्लेख नहीं है ।" (226)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीन मजदूरों की दशा के सम्पूर्ण सुधार करने और उन्हें जीवन में स्थायित्व प्रदान करने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है ।" (227)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जातीयता, भेदभाव, अस्पृश्यता के उल्लेख पर, स्कूल और विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तकों में सदैव के लिए प्रतिबन्ध लगाए जाने की मांग का उल्लेख नहीं है ।" (228)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े भारतीय अथवा विदेशी पूंजीपतियों के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग का उल्लेख नहीं है ।" (229)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू तथा कश्मीर, नागालैण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा जनता की सुरक्षा तथा अन्य सुविधायें दिए जाने के सम्बन्ध में सरकार की निन्दा का उल्लेख नहीं है ।" (230)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीन द्वारा वियतनाम पर खुला सशस्त्र आक्रमण कर सम्पूर्ण मानवता के प्रति घोर अन्याय किए जाने तथा चीन को आक्रामक घोषित किए जाने और मात्र चीनी सेनाओं को वापस जाने को कह स्वतन्त्रता प्रेमियों की निराशा का उल्लेख नहीं है ।" (231)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के दलित, आदिवासी, हरिजन और गरीब वर्ग की बस्तियों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता तथा उन्हें आदर्श रूप से पुनर्वासित करने का उल्लेख नहीं है ।" (361)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों में अनुशासन, निर्भयता और सुरक्षा की भावना की कमी, जिससे राष्ट्रीय प्रगति में बाधा पहुंचती है, का कोई उल्लेख नहीं है ।" (374)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संपूर्णक्रान्ति और उस बारे में सरकार की नीति का कोई उल्लेख नहीं है ।" (375)

[श्री केशव राव धोंडगे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय जनता की मूल जरूरतों जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, आवास तथा अन्य छोटी-छोटी सुविधाएं देने में सरकार की असफलता और इस प्रकार लोगों के मूल अधिकारों की उपेक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।" (376)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के एक बी० के० कोपले विद्यार्थी पर विदेश के एक विश्वविद्यालय में हुए दुर्व्यवहार और बर्बर आक्रमण जिससे उसे विदेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, कोई उल्लेख नहीं और अनेक भारतीय विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति।" (378)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में डा० बाबा-साहेब अम्बेदकर की मृत्यु की जांच के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट को प्रकाशित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (379)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद् के लिए अलग शिक्षक चुनाव कालेज की मांग का कोई उल्लेख नहीं है।" (380)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आपातकाल का विरोध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जेलों में तथा उनके बाहर किये गये अत्याचारों के लिए महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने और उनके द्वारा आपातकाल में अत्याचार करने और तानाशाही का खुलेआम समर्थन करने के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।" (392)

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं प्रस्तावित करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी पदों पर कुछ गिने चुने उच्चजातीय लोगों का प्रभुत्व समाप्त करने और उनमें पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है।" (71)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार, असम, मेघालय तथा देश के अन्य पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों का द्रुत विकास करके क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है। (72)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त अव्यवस्था और असंतोष समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।" (73)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त बढ़ता भ्रष्टाचार रोकने और नौकरशाही के बढ़ते प्रभुत्व को कम करने का उल्लेख नहीं है।" (371)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनता सरकार के दो वर्ष से सत्तारूढ़ होने पर भी बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए किसी रचनात्मक और समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।" (372)

SHRI SAUGATA ROY: (Barrackpore): I beg to move:—

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret the absence from the Address mention of gruesome happenings at the Assam-Nagaland border and concrete steps to be taken by the Government to sort out the Assam-Nagaland border dispute." (118)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address makes no reference whatsoever to recent happenings in Jammu and the concrete steps to be taken by the Government to solve the problem of regional imbalances between different regions of the border State of Jammu and Kashmir." (119)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address makes no reference whatsoever to the industrial unrest in different parts of the country including the continued strike in the jute industry and the

threatened strikes in the textile and coal industries and concrete steps taken by the Government to create a better industrial climate." (120)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address makes no reference whatsoever to the plight of the Dandakaranyas deserters in Sunderbans and the concrete steps taken by the Government to solve the residual problems of the refugees from erstwhile East Pakistan." (121)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address makes no reference to the problem of sharp fall in prices of agricultural commodities and concrete steps taken by the Government to ensure a fair price for agricultural commodities." (122)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address makes no reference to the urgent need for implementing the land reform laws." (123)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not contain any specific reference to the increase in assets of monopoly houses and concrete steps taken by the Government to prevent further concentration of wealth." (124)

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address of the rising trend and increasing intensity of communal violence against the Muslim minority in several parts of the country like Aligarh, and fails to indicate what specific steps the Government propose to take to maintain law and order and also to promote communal amity and harmony." (135)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not assure that the Muslim minority character of the Aligarh Muslim University will be duly restored in deference to the most justified persistent demand for the same." (136)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address of the recommendations of Gujarat Committee for Urdu and of the need to give Urdu its due and just status." (137)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address fails to indicate any proposals to enable the Muslim minority to secure economic and educational justice and fair participation in Government and other services." (138)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address of the hardships faced by those who intend to go abroad for employment and the pressing need for revision and relaxation of emigration laws and rules." (139)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address of the recent thoughtless and arbitrary cancellation of a large number of trains in the Olavakot Division of Southern Railway leading to public indignation and widespread agitation." (140)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address of the reports

[Shri G. M. Banatwalla]

and recommendations received by the Government from the Minorities Commission, especially reports with respect to Aligarh riots, riots at Pernambet (Tamil Nadu) and Aligarh Muslim University." (141)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address fails to assure that the Minorities Commission will be expeditiously armed with adequate statutory powers." (142)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address fails to extend greetings to the people of Iran for their glorious and successful revolution for democratic rights." (370)

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address makes no reference regarding the sub-plan for tribal areas of the country which aims at to eliminate all forms of exploitation of tribal people by the State Governments as well as by the Centre." (241)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not indicate any concrete step for solving the problem of administration, both financial and developmental in tribal areas of the country which is the responsibility of the Centre and States." (242)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not mention the planning, programmes, allocation and implementation for the upliftment of the the tribal people and devlopment of the tribal areas to bring them in the mainstream of the national life." (243)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the role of the Government, particularly of the Central ministries, regarding the sub-plan for tribal areas of the States and indication of the allocation by the Ministries for these areas in five year plan and annual plan." (244)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not recognise the fact that due to failure of the Government to implement the land reforms, the problem of the landless people of the country increased and the discontentment among these people is increasing and they are the victims of the vested interest people."(245)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not indicate a clear, bold and pragmatic socio-economic policy for the Adivasis, Harijans and backward class people of the country" (246)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not make any reference about the district and block level planning and implementation." (247)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the tribal languages and scripts and their preservation and development by the Government by providing necessary help to these written tribal languages." (248)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention of allocation earmarked for tribal areas, backward areas, hilly areas, border areas, drought prone areas, and the undeveloped areas and the strategy adopted for the development of these areas to bring them at the level of developed areas in the States."(249)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no sufficient emphasis in the Address on the crucial and urgent need of the weaker section of the people particularly of tribal and Harijans." (250)

SHRI INDER SINGH (Hissar): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about implementing the Government Award, 1976 about the distribution of Ravi-Bisa waters between the States of Punjab and Haryana." (151)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the transfer of Fazilka and Abohar areas of Punjab State to Haryana State in accordance with the Central Government Award in 1969." (252)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the rationalisation of the prices of Agricultural produces so as to bring them at par with the prices of industrial commodities." (253)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the implementation of land reforms measures." (254)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Addres there is no mention about eradication of poverty and unemployment in the country and for giving unemployment allowance to the unemployed educated youth." (255)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the measures being taken to check steep rise in the prices of agicultural inputs, implements, insecticides and pesticides and steep fall in the prices of agricultural commodities like cotton, sugar and potatoes which has adversely, affected the agriculturists." (256)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about rampart corruption, nepotism and favourtism in the country." (257)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the transfer of the control of the Irrigation Head Works located at Ropar, Harike and Ferozepur to the Bhakra Management Board to ensure a fair measure of water and power supplies to Haryana." (258)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the nationalisation of big and key industries and ending of monopoly houses in the country." (259)

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the improvement of the position of Labour Management Relations and that some of the provisions of the Industrial Relations Bill are against the interest of the workmen." (317)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address of the need for making the Indian Ocean a zone of peace." (318)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address that the number of unemployed people is increasing day by day." (319)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the disturbances in Border areas of Assam, Nagaland and Tibet." (320)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address that in spite of our cooperation with the neighbouring country like Bangladesh there has not been a happy settlement in regard to distribution of Farakka waters." (321)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address that if the Chinese forces do not withdraw from Vietnam the Government shall bring this matter before the Security Council for immediate settlement of the issue as peace in Asia, particularly in South East Asia, is in great danger." (385)

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): Mr. Speaker, Sir, I rise to oppose this motion.

Sir, the President's Address is supposed to be and ought to be the State of the Union Message to the Nation. It should not be party document, it should fully and faithfully reflect the conditions existing in the various sectors of the nation. So, in approaching this Address, the touchstone should be whether the important areas concerning the nation have been adverted to, whether through the report a truthful picture of the nation has been truthfully placed before us, and whether a very correct picture of the conditions obtaining in the country has been presented to the Parliament. My own assessment is that this is a very laconic Address, full of complacency, absolutely unjustified, and if I may say so, Sir, this Address is guilty of *suggestio falsi* and *suppressio veri*. Half-truths have been spelt out, truths have been kept back, important areas in the national life....

SHRI M. SATYANARAYANA RAO (Karimnagar): Sir, I will request you for one thing. He is not doing well. So, he should be allowed to speak while sitting.

MR. CHAIRMAN: You can sit and speak.

SHRI C. M. STEPHEN: If I feel like that, I will seek your permission.

This is what I have to say primarily about this. The social tensions mounting in our country, the law and order problem in our country, the unemployment problem in our country, the conflicts which are developing in our country, the conflict between State and State and States and Centre which is now assuming proportions in our country, the tendencies of disintegration that are setting in in the different regions of our country, and the very dangerous situation in which, in the international context, we are today placed — these have not been adverted to at all. The President should have adverted to these. That there is

this deficiency in the President's Address is acknowledged by quite a number of Members from the ruling party itself, if one goes by the amendments that they have given notice of. Therefore, I will be untrue to myself if I am to say that I am thankful to the President for presenting a true, faithful and honest assessment of the situation in our country.

Complacency has crept into the Government. Governments may come and governments may go, but this sort of complacency is absolutely dangerous. Of course, conditions were very favourable when the Government took over. We had the foreign exchange reserves, we had surplus foodgrains with us, production was very much on the high side, we had inflation contained, things were fairly all right, technologically our country had come to the third place in the comity of nations, industrially we had advanced to the eighth place in the comity of nation. The foundations had been laid, and we could have taken off, we were on the take-off stage. These two years, the weather God has been very kind to us and therefore the targets which were fixed by the Fifth Five Year Plan—we are on the last year of the Fifth Five Year Plan, let us remember that —have been reached.

My hon. friend was saying that 125 million tonnes of foodgrains have been produced. I would just remind him that if you go through the projections in the Fifth Plan, for 1978-79 food production was projected to be 126 million tonnes. You can go through every item, I have done that exercise. Therefore, I am saying that the achievement which has been attained is nothing unexpected. This was projected, and there were projections for the next two Five Year Plans also. Once we are on the take-off stage, we can go on to that area. If my friend claims that the 126 million tonnes of foodgrains just dropped from the air out of the effort made in the last 12 months and irrigation came up just like this, I have nothing more to say.

I was also astounded when the mover of the motion said that in the last year 6 1/2 lakhs of hectares were distributed, I would just remind him that 6 1/2 lakhs of hectares distributed was upto November, 1978, from 1951 onwards. I do not blame my friend because it is spelt out like that in the Address, it is given in a manner which would give the impression that this was given in the last one year.

Take the economic conditions. The President has given a picture of all is well and all is smilling, but there are certain very vital aspects which the nation must take note of. I have with me the Report on Currency & Finance of the Resereve Bank of India, a very authoritative document. They say:

> "While the growth attained during the year was better than the annual average rate of about 5 per cent envisaged in the draft Plan, its composition was strikingly unbalanced which may suggest difficulties in sustaining the rate in the remaining years of the current Plan period. The growth for 1977-78 was considerably on account of agriculture and the record agricultural output in turn followed principally from the favourable climatic conditions."

In had a discussion with certain persons of the Planning Commission. The Fifth Five Year Plan had projected that our development will be of the order of 5.7 per cent or so. The current Plan said that it is not possible to attain that level. They had, therefore, brought it down. We said that unless we attain a growth rate of 5.7 per cent, we cannot reach full employment. Anyway, we are not going to reach it. That is what they have said. The Reserve Bank document has this to say:

> "In contrast the industrial growth rate was disappointing. The spread effect of agricultural production was felt to some extent in industry, especially in the sugar industry. But

[Shri C. M. Stephen]

the over-all indutrial growth was only about half of that attained in the previous year. In the last report certain features were cited as influencing substantially the growth in the industrial output recorded that year. During the year relevant to this report, some critical sectors were principally responsible for slowing down the pace of industrial growth, not necessarily in the order in which they have been listed."

Therefore, when we say that there is a national income explosion coming up and all that, we must not forget the fact that there is a weightage, which is a factor you take into consideration when you are fixing up the indices. Agricultural part has got a substantial weightage. When that goes up the indices of national income goes up. What is the positive effort made for having idustrial advancement is the question? There the Report says that there has been a slide back.

"Sluggishness and uncertainty mar the psychology which prevailed during the year as a whole. According to the provisional estimates of 1977-78 made by the Reserve Bank, despite money incomes growing at a higher level than in the previous year, the aggregate domestic savings showed a decline of 5 per cent. As in the past two years, aggregate savings exceeded domestic investment in 1977-78 also."

So we have got a picture of the domestic savings coming down and the investments still coming down. These are the figures: 1975-76 domestic savings 15.6 per cent investments 15.8 per cent 1976-77—17.9 per cent and 17.1 per cent, 1977-78—15.6 per cent, savings has come down and the investment has come down still further to 14.2 per cent. Investment has come down although there was higher national income and all that, although there was wealth in the country, although there was saving, no investment was taking place. This is the bleak picture that we have got to see.

"A feature of consequence to the economic outlook for the immediate future is the pronounced slackening in the pace of accretion to the reserves in the last quarter of financial year. In the quarter, April—June 1978, the Reserve Bank's foreign currency assets rose by Rs. 19 crores only while the increase in the immediately preceding quarter was Rs. 501 crores and that in the corresponding quarter of the previous year was as much as Rs. 719 crores. The growth in exports in 1977-78 is placed at 4.5 per cent. This was sharply down from the wrowth to 27.3 per cent in the preceding year At the same time the prospect in respect of non-merchandise receipts which have contributed substantially to the growth in the reserves in recent years is somewhat missed."

Here I may mention one thing, about foreign exchange expansion. Export balances, we have got, remittances, we have got and then income from tourism and other non-perceptible incomes, these are added upto constitute our foreign exchange balance. But the particular matter that is emphasised today is that remittances from Indians abroad are fast dwindling and the deduction by the Economists is that this shows that the money is being funnelled through smuggling. It is not that people are not remitting, not that people are not going abroad, they are earning, but the earned money is now being remitted back by underhand dealings and the Reserve Bank is not getting the foreign exchange. I am not making that allegation. I am only saying that there is an allegation. But the fact remains and it has been shown by the report placed on the Table of the House that the public sector which has earned such a substantial profit for one or two continuous years has today started incurring a loss. This position gives credence to the allegation. And remember that Public Sector is the only area where we could make any progress forward.

You will have to lok at the black money and the blackmarket. What is the money supply position? In the last year's President's Address, which is before me, a very great claim was made that money supply was brought down. This was the great claim made by the Government in the last year. What is the position today? This is what the Reserve Bank says, I again quote:

"The period between end-June 1977 and end-June, 1978 was characterised by unprecedented expansion in money supply with the public and money supply with the public expanded by Rs. 3100 crores between end-June 1977 and end-June 1978 surpassing the previous highest expansion rate of 17.3 per cent registered in 1972-73."

The money supply was brought down..this was the claim made last year. But today nothing is mentioned about it. Money supply has rocketed up and in an explosive manner money supply has gone up. This is the position. What are the inferences from this? I am saying that blackmarket is today flourishing. You look at the prices of real estate in any city. They are rocketing up, look at the blackmarket prices of cement, of commodities like soda ash. Blackmarket is flourishing.

Smuggling is therefore mounting up. This is the position regarding balance of trade.

"For the year as a whole imports registered an increase of 19.6 per cent while in the previous year they have declined to 1.6 per cent. As the policy of liberalisation is extended and its effect....imports may be expected to continue to rise."

After commenting that the present level of foreign exchange appears to be comfortable, the document has mentioned so many factors and concluded:

"Seen in this light the country's foreign exchange reserves cannot be considered to be abundant. The recent developments of the quantum of export-import trade and the pace of reserve accreation underline the need not to be complacent about external payments position."

This is the picture which the Reserve Bank of India has given. They have also commented about all the inducements given to the capitalists, all the inducements to the industries and observes: "industrial licence requirements have been released, import libiralised, revival of new issues through tax benefits for investment in new capital issues, lowering of the interest rate structure has brought down the cost of credit."

Still, the investment is not coming up. And they comment:

"However, it is only, as the public sector investment outlay as proposed under the Plan gained momentum and their spread effect is established that the economy would be fully freed from the present state of sluggishness."

What is the condition of the public sector? About the public sector, a report has been placed on the Table of the House and an extract was published in the *Patriot*..I saw that I checked up with it. That shows that there is a loss of Rs. 14 crores as against the profit of Rs. 390 crores in the previous year. There is an allegation that this Government is not favourably disposed towards the public sector. Now, this is a matter which we have got to take note of. If you go to Bombay, Calcutta or Madras, you will find that the smuggled goods markets which had earlier completely disappeared—are today flourishing. Smuggling has become a respectable job. Now openly these transactions are taking place and valuable foreign exchange is being smuggled away. This is an appalling position which we are witnessing today.

SHRI ASOKE KRISHNA DUTT: Much less than during the Emergency.

SHRI C. M. STEPHEN: Forget about it. You can carry on your *mantras* about Emergency. But how long can you do that? Every year in the President's Address, one after the other, you go on saying "democratisation, giving freedom to the press, lifting the Emergency". But on the other hand this is the position. Behind this smokescreen, this is what is happening. Should I not point out that? I am just pointing out that this is what is happening. I am not saying this. I am reading from the Reserve Bank Bulletin. Let us remember that everyone of us is sitting on the crater of volcano. May be I am responsible, may be you are responsible or may be all of us are responsible. I am speaking of the unemployment problem. Morarjibhai stated his regime with a promise of wiping out unemployment within ten years.

Now, two years have gone by. Should he not tell us, should not the President tell us, to what extent, in what manner, in what area, unemployment problem has been tackled, educated unemployment problem tackled, rural unemployment problem tackled? The persons who are depending on the rural economy, should in a healthy economy, progressively shift away from the rural areas to the urban areas. Has that happened? Has unemployment come down to any extent in rural areas or urban? Should not there be some reference about it?

What is the tremendous size of the unemployment problem? Here is in my hand the present Five Year Plan It says:

> "The labour force in 1978 is expected to be 265 millions .... an annual addition to labour force of the order of 5 millions. Assuming the present-day unemployment, in March, 1978, it should be 20.6 million persons yearly, 16.5 millions in rural areas and 4.1 millions in urban areas.

These are clearly the most conclusive figures. This is the size of the unemployment problem that we are facing today. Every year, 7 million hands are being added on and a substantial part of them, educated unemployed, are going about searching for jobs. They are not getting the jobs. I am not blaming anybody. But as a Parliament of the nation, we have a ponsibility to take note of the fact and to realise that the things are not that easy. There is no justification for complacency. The youngmen who had educated themselves are going about with a begging bowl for a job of Rs. 80/-, doing whatever they chose, getting nothing. They have no meaning for democracy they have no meaning for Parliament. This is the position that has come about. Let us realise that.

The President has not cared to point his finger to that, to what extent this has been done. I have checked the figures on live employment register. It shows a pick-up, not a fall. In the last two years, the figures on live registers show a pick-up in the number of people who are waiting for employment. Therefore, the unemployment problem is terribly back again on our neck.

Much has been said about price stabilisation. The indices are there for the wholesale prices. Everybody is speaking about the wholesale prices. But what about the consumer prices? My hon. friend, Prof. Mavalankar and others were shouting at us when we were in power, saying. "There is rocketing of prices." That was in 1974-75 when the inflation was at the peak. In 1974-75, the consumer price index was 317 for industrial workers; In 1977-78, it was 324 and in June, 1978 it was 327. I just now went to the Library and checked up that in September 1978 it was 336. This is the way the consumer price index for industrial workes and manual employees is go-

ing. It has crossed and gone far ahead of the worst peak ever. It is higher now than what was ever before. This is how it is going on.

You have claimed stabilisation in the wholesale prices and that is because of the weightage manipulations there. The agricultural prices are lower because there is bumper production. The Reserve Bank speaks of the considerable effect on the wholesale price index by the bumper production in sugarcane and the consequent fall in the price of sugar. The cane grower does not get his price. The pice is low. Therefore, the whole thing has slumped down. As against this low level of the prices of primary articles on the one side what is the position in that group known as industrial goods on the other? We have to see these two groups separately.

As far as primary articles are concerned the prices are going down. As far as agriculturists are concerned, the cane grower does not get his price; the paddy grower does not get his price; the cotton grower does not get his price. These people do not get their price. On the other hand, as far as the agro-industrial products are concerned, if you look at their prices, their prices are moving up. What does it mean? It means that the rural area is being exploited. The money is being drawn out from the rural areas and pumped out to the urban areas. Much is spoken of special protection to the rural sector.

It is only lip-servicing. The rural area in business is only lip-servicing. Talking of industrial materials, in the case of paper there is 8.8 per cent increase, in the case of leather 19.2 per cent increase, in the case of rubber products 20.4 per cent increase, in the case of industrial materials 13.4 per cent increase, in the case of mineral products 14.4 per cent increase, in the case of basic metals 12.9 per cent increase and in the case of textiles, 12 per cent increase. The cotton price goes down but the textile price goes up! Where does it go? Who takes the money? It is a case of the agriculturists being exploited. And for that purpose, Rs. 400 crores has been paid to import cotton, just to sustain the textile magnates.

About rubber, the Keralites know about the case. When a slight increase in rubber took place, immediately rubber import took place. Even at a higher price rubber was imported, just to suppress the price of rubber.

So, this is the policy followed. For primary products there is a particular price level, for industrial products there is a particular price level. The consumer cost of living is moving up but the whole-sale price is being illusorily kept steady—because of the heavy weightage from agricultural products that you obtain. This is the economic condition that one can see. Therefore, all I am saying is that there is absolutely no scope or justification for complacency.

Now, leaving alone the economic situation—the economic situation is not good but is appalling—in the meanwhile, we attempted the experiment of gold sales. Is there any mention about this? Such a furore was raised in this country. but there is no mention about it. It was said that gold was imported; is there any mention about it? What happened to that gold? Why was it imported and why was it sold? There is no explanation; the president does not make any mention at all.

Therefore, as far as the economic condition is concerned, we are in for an inflationary spiral. The moment the weather God ceases to smile and he starts to frown, then the inflow of the money supply, the lack of foreign exchange, the smuggling which is operating, the black-money which is mounting, the tunnelling way of the foreign exchange remittances, the importing which has assumed a considerable level, will together start suffocating us and the flood gates of in-

[Shri C. M. Stephen]

flation will open. Liberalisation of imports was attempted; at whose cost, I am asking. When liberalisation of imports of consumer goods was attempted, did the Government make an assessment of the small industries that were affected by these imports, of the small industries that have been closed because of these imports, of the small industries which are not able to stand up to the competition because of import of consumer goods which could be produced here? There are umpteen such industries.

Now, there is a wonderful piece which I saw in this speech, saying that for employment purposes District Industrial Centres have been started. What I understand about the District Industrial Centres is that they are an expert body assigned the task of giving expert advice. But the President is given some other impression: the President is given the impression that these are employment-generating industrial organisations. That is the ignorance that is being displayed. The District Industrial Centre is not for that purpose at all. Anybody who knows anything about the District Industrial Centre knows enough—to know that it has employment potential just for the clerks and the people who are employed there; nothing more than that. Nothing else would be forthcoming from that. It is absolutely clear.

Therefore, I would appeal to the Prime Minister and the Members of the ruling benches not to be complacent. The point is, even if everybody went to sleep, production would have been there. But how you make use of that is the question. There, if you look at the export figure, if you look at the foreign exchange figure, if you look at the remittances figure, if you look at the money supply figure, if you look at all these, you will find there is mis-management of economy.

Coming to the national scene, the past year was a year of tension and strife. Can there be any denying of that? Social tensions, language tensions, territory-to-territory tensions, interest-to-interest tensions, fights and conflicts, communal clashes, and so on. It was yesterday that the Home Minister told us in this House that, in 1978, a total of 412 Harijans were killed and 478 Harijans were raped. This was the answer the Home Minister gave to Parliament yesterday. It is a matter about which you can be complacent? 412 Harijans were murdered and 478 Harijans were raped! This is what is should here. The Janata Party, in its National Committee Resolution, has said that any Government which is not able to protect the life and property of its citizens does not deserve to be there, does not have the right to rule. It is a first class dictum! May I ask you this: are the Harijans human beings or not? Are their properties not the properties of humanbeings? Or, are they chattels? Is it that only if somebody else is attacked and killed, then alone murder of humanbeings takes place? If that is the standard, which Government would have the right to continue, I ask. Can you continue?

SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR (Bombay North-Central): Speak about the Andhra MLA.

SHRI C. M. STEPHEN: Don't come out so feverishly pleading for them! Shall I speak of West Bengal? You are not in the dock for the time being.

Now, Sir, if it is Andhra, if it is Karnataka, if it is Bihar, if it is U.P., well, if you have got the responsibility, report to the nation. That is what I am saying. Why suppress this in the President's Address? That is what I am asking. Is it not a matter of serious importance to be reported to the nation? If that has happened in Andhra, report to the nation, if that has happened in Karnataka, report to the nation; if that has happened in West Bengal or U.P. or Bihar, report to the nation. The President's Address should not have left out mentioning the murder of 412 Harijans and the rape of 478 Harijans. Do not treat them as if they are not humanbeings at all.

I am only saying that human tensions have been mounting up, atrocities have been taking place: Communal clashes, not only in Aligarh but also in other areas, have taken place. Language tensions have been taking place and the Prime Minister, in his own way, has been adding on a little ember to the fire. I do know that somebody was killed in Pondicherry. Who was responsible for that, I am asking. Now, the Prime Minister went and said there that it was going to be merged, and subsequently he says that it is his personal opinion! I do not understand this. Is the Prime Minister of India, Mr. Moarji Desai, a 'personal opinion man?' Can be merge Pondicherry on that basis? It is only the Prime Minister who can do that. Now, as a result of firings that took place, I think two or three persons were killed, and property was also looted. Even my friend Mr. Bala Pajnor was harassed about it. These things took place. I am only asking why is this tension taking place.

Last time when we adjourned, we adjourned taking a very serious note of the atmosphere of violence prevailing in this country. It was I who spoke almost last, I did not take a partisan-stand on that, I said, this was a matter which should be taken note of. Subsequently, what happened? Somebody goes and attempts to murder Mr. Charan Singh, somebody goes and attempts to murder Mr. Yadav in U.P. Political murders are being attempted. Political murder is becoming a cult of our life. Tensions have been taking place. Therefore, I say, this tension is a matter of very great importance.

15.00 hrs.

Now UP, Bihar and then backward and forward community tensions are taking place. Sir, I do not find fault with the forward community people in resisting. I do not find fault with the backward community people demanding, because there is so little to go around. Everybody is in need of some job to sustain himself. Unemployment is rampant. Therefore, every job is valuable. And when reservation takes place, people fight one another. But I am asking: what is your policy in dealing with these social tensions? The problems of social tensions and your policy have led to a certain situation in which law and order has broken down, people have been killed, educational institutions are affected, communications have been disrupted, people have been murdered—all these are taking place everwhere. The way you handle the social tensions is the most damaging and dangerous way. This is nothing that is creditable for the government. That is what I am saying.

Another point is corruption. I am seeing, in the last Presidential Address there was this magnificent dictum spelt out:

> "People earnestly yearn for cleaner politics and cleaner administration at all levels. Unless there is faith in the probity of the holders of high offices, the future of constitutional government will not be secure".

What a magnificent dictum! But did you apply this dictum last year? May I ask this question to the Cabinet Ministers sitting here? What was the thing that created the whole Cabinet tension in 1978? This is the dictum and Mr. Morarji Desai defends his son! I am not saying that he is corrupt or he is not corrupt—that is not my job—but I am taking the total fact that his Home Minister said. In order to clear the air, there must be an inquiry' and the Rajya Sabha passed a resolution that there must be an inquiry. He resisted; as a result, subsequently, Mr. Charan Singh had to go. Mr. Charan Singh said, 'I was surrounded by corrupt people in the Government'. Mr. Charan Singh has not withdrawn his statement. Mr. Charan Singh has come back and the corrupt people in the government being there, corruption-accusing Mr. Charan Singh is back sitting among the corrupt people again. Corruption is there. If this dictum is applied, where are we? I am

[Shri C. M. Stephen]

asking. Corruption has to-day become the law of the land. If you are not corrupt, you are not smart enough. That has come to that. It has come to that situation. And the poor man, the jobless man who is hunting for a job, looking at all these luxuries is feeling desperate, and frustrated. This is the point I am emphasizing and if non-corruption is the standard, would Morarji Bhai, the honest man that he claims to be, claim that his government is free of corruption? Would anybody claim that? I do not want to add anything more to that. I would rather leave it at that.

Again, the most disastrous aspect of it is that we are fast losing the sense of one-ness which must knit this country together, South is speaking of south; north is speaking of north. Take the North-eastern area. Wonderful. I have got a resolution to-day by somebody. Assam Rifles and everybody there going to Meghalaya, capturing some property and sitting over there. And Meghalaya demanding their evacution and they say the Government of India does nothing. A State sending its forces to another State, driving out the people from there, taking over the property and sitting there and running the administration! A boundary dispute, not between India and China, but only between Meghalaya and Assam and Assam and Nagaland and between different States and the States taking the law upto themselves! I am saying segment consciousness is developing. Every body becomes acquisitive because everybody is feeling unsafe and everybody is feeling unsafe as everybody is developing an acquisitive consciousness, one against the other..... (*Interruptions*).

Well, Sir, again I may say here that it so happens that in the Government of India to-day that hemisphere of India which is South of India is not represented here. Of course Mr. Ramachandran is there. But that is not enough; that is not the representation in Government here. The people in South to-day have started tasting as to what is going to happen; what will happen if the North assumes the power and runs the whole country? I am saying about the major responsibility in this respect. I am not trying to foment on the South-North feeling. But, the fact of life lies there; the fact of life is that the entire South is away from Government.

Now, against that background when you are saying that we are looking into the problem of Hindi—you said there will not be Hindi imposition—they are now feeling that the Hindi imposition is being done. This is a question of getting away of one from the other. There is an attack on Harijans. There is insecurity. Landless labour are afraid—no sense of security; minorities are afraid because there is no sense of security. When brutality prevails, others have no sense of security. If this happens in a large country like India which has got its own diversity it can be held together only by a sense of fairness all-round, justice all-round —whether big or small, whether major or minor. If that does not happen, that is the bad day for the country. I am seeing the signs of development of that sort of a feeing of alienation and therefore I say it is time that we take note of this also.

Now, Sir, finally, when all these things are taking place what is the way out? The way out is that there must be a proper leadership. The leadership there must be—can you claim anywhere that type of leadership—we are getting? Well, Sir, before you ask me this question, let the Prime Minister say whether his leadership in the Cabinet itself is accepted or not. Is anybody prepared to take up the position and say that the country must have that lead? There is no homogenous concept in the Cabinet itself. They are pulling in different directions. Honestly they believe in different political and economic philosophies; honestly they pull against one another; honestly tension is mounting; honestly they are parting companies; honestly they are coming back

again in order that they remain together. This is what is happening today. (*Interruptions*). That is not the leadership the country needs and when that leadership is not forthcoming, what happens? The organised sector gets the upper hand; big money gets the upperhand. Definitely it will get the upperhand. The organised political forces get the upperhand. That is why the whole Jan Sangh section—R.S.S.—is getting a complete hold on the life of this country because there is an anarchical condition prevailing; everybody is depending on somebody else. They know their job; they are going ahead and they are making themselves felt. When Morarjibhai protested in Rajya Sabha to any reference to anybody, Mr. Advani decided that he must chip in. He did it. Morarjibhai said a Committee of three is coming; send it to somebody to look into it. In the U.P. also they decided that and they got it done. They are going to do that in Bihar everywhere. They are demonstrating everywhere that they who are masters matter in this country because they are the organised section. That organised section has finally complete hold on the economy and in the national life of this country. This is the basic danger on the political and social life which we are facing. And on the other hand, the other people become desperate, despondent. They are going helter skelter and the nation is at the cross roads. I entirely agree with Mr. Dutt when he said that the nation is at cross roads. It is on the cross roads on the financial basis, economic basis, industrial development basis and planning programme basis. On every basis we are at the cross roads and the biggest danger is the menace of a fascist take-over starting in our face. I am very clear about that. That is the danger that is starting us in our face. It is time we awake to that.

Therefore, the total picture that presents itself to us is not one for complacency. It is one for great thinking and for great acting.

Democracy you are speaking about! My friend, the mover of the motion, charged me for boycotting the President's Address. Well may I ask him what his party did in Andhra Pradesh? The Governor, a very weak and sickly man form my State—a very respected guru of ours—who could not stand up to it spoke one sentence then the second sentence and then had to drop it and go. Why? Their party prevented, raised noise, created obstruction and he was prevented. What happened in Karnataka Obstruction took place. How long! Trritrivably obstruction took place. In different areas it took place. (*Interruptions*). . .

Well, Sir, we are the Opposition. You are the ruling party. You are now telling me and, therefore, I am telling you behaved that way when you were in the Opposition. You behave that way even today when you have assumed power here. Wherever you are in Opposition you behave that way. Whereas we had only lodged our own protect. (*Interruptions*).

Would you not concede that in the matter of the resolution passed against our leader we were deeply aggrieved? And yet we merely protested in silence. What was your standard of behaviour? On the one hand, a resolution passed by Rajya Sabha government does not accept. On the other hand a majority here puts out member who is elected here. On the one hand government ignores the decision of Rajya Sabha and on the other hand the majority here ignores the decision of the electorate. Wherever you are in majority you use it in order to ignore and to curb the Opposition even if they have got the right to protest. Here you ignore the electorate and there you ignore Rajya Sabha. Government ignored Rajya Sabha, majority ignored the electorate. This is democracy! You are doing that in Andhra Pradesh and Karnataka and you are speaking of democracy. This is the democratic set-up! Well, carry on with your democracy. You can carry on with the democracy but a situation in which a person elected by the people will not be permitted to sit that sort of democracy will have its

[Shri C. M. Stephen]

soil eroded from under-neath. That is why on the expulsion motion seasoned parliamentaries like Shri Kamath and Prof. Mavalankar refused to vote for that and said that they have being to do with this. That attitude they took Well, this is the beginning of the erosion of democracy. By what you did in Karnataka, what you did in Andhra Pradesh and what you are doing in different areas, what you did in Rajya Sabha and what you did in Lok Sabha you are putting the axe on the trunk of democracy in this country. We have to protest against it. We acted. We did not come and make noise. We know many friend on the other side who, I remember, thumped and prevented the speech taking place. We know that. But we quietly kept out. We went to the President and presented a memorandum and told him that we will not be able to come, Sir, because of this concientious difficulty. What is undemocratic, about it? Absolutely none. If we did not do it we would not have been true to our conscience and so we exercised our right.

Therefore, Sir, this document is a master-piece of *suppressio veri* and *suggestion fall*. It is master-piece of suppressing facts and issues that concern the nation. It is a masterpiece of evading issues which should have been brought to the notice of the nation. It will remain as a document which is not honest to itself, not honest to the nation. It will remain as a document which has given a wrong picture of complacency to the country and this spirit of complacency that underlines the document is the Government. This being the truth about this document it represents all the elements that will prove to be the benumbing illusion overshadowing beginning of the end. With these words, and for these reasons I oppose this Motoin

सभापति महोदय : आप अपनी बात 10 मिनट में कहने की कृपा करें ।

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति जी, यह तो मेरे साथ सरासर अन्याय है

सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये भाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय स्टीफन का जहां तक सवाल है उन्होंने कहा कि वह भाषण का विरोध करते हैं। हम ऐसी आशा थी क्योंकि विरोध पक्ष का नेता बनने के पूर्व वह इन्दिरा गांधी का भी विरोध करते रहें हैं। और जब विरोध पक्ष के नेता बन गये तो इन्दिरा गांधी के प्रति उनमें प्रेम पैदा हो गया, उनके समर्थक हो गये। इसलिए समय समय पर इनके विभिन्न स्वरूप होते हैं। कोई रचनात्मक आलोचना से इनका वास्ता नहीं है। इनका एक ही काम है कि सरकार के कार्यक्रमों की आलोचना करें। और जितने भी सम्मानित सदस्य यहां हैं वह जानते हैं कि जब यह विरोध पक्ष के नेता नहीं थे तो उससे पूर्व इनकी भाषा का तारतम्य कुछ दूसरा ही था। इसलिए अगर वह हमारी सरकार की आलोचना करें तो मुझे कोई शिकायत नहीं है।

जहां तक कानून व्यवस्था और अन्य चीजों का सवाल है इन्होंने कहा कि पूरे देश में एक वातावरण तैयार किया जा रहा है कि इस देश को इनके अलावा और कोई नहीं चला सकता, और पूरे देश में एक मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया जा रहा है कि इन्दिरा गांधी ही एक मात्र ऐसी नेता हैं जो देश को सही हुकूमत दे सकती हैं। सभापति जी, मेरी एक अपनी कल्पना थी और मैं ऐहसास करता था कि इन्दिरा गांधी ने जो कुछ किया अपने बलबूते पर किया और उसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन इनकी जो भाषा है उससे ऐसा लगता है कि इन्दिरा गांधी का दिमाग खराब करने वाले यही लोग हैं। हर वक्त बारबार यह कहना कि एक नेता है, पार्टी में कोई तारतम्य नहीं है। इसका क्या अभिप्राय है? पूरे लोकतंत्र की बुनियाद एक व्यक्ति में निहित कर दी जाय, और कोई मतलब नहीं है। और यही कारण है कि देश में जो कुछ हुआ इन जैसे ही लोगों ने इन्दिरा गांधी का दिमाग खराब किया। मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि वह पूरी प्रक्रिया को एक बार सोचें, इन्दिरा गांधी को सजा हो या न हो, कम से कम इन लोगों को दण्ड देने का जरूर इंतजाम किया जाना चाहिये। संजय गांधी का बुद्धि से कोई वास्ता नहीं था, मोती लाल नेहरू जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गांधी से जोड़ कर और देश के सामने एक नक्शा पैदा किया कि इस देश को नेहरू परिवार के अलावा और कोई नहीं चला सकता। इस प्रक्रिया को शुरू करने वाले इन्दिरा गांधी नहीं यही लोग हैं।

जहां तक उत्तर प्रदेश और बिहार का सवाल है वह हमारी पार्टी का आन्तरिक मामला है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी किसी व्यक्ति को लादने के पक्ष में नहीं है। अगर

यहां के विधायक यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति सक्षम नहीं है और उसको बदलना चाहिये तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के समान मेम्बर जो लोक सभा के सदस्य हैं जब कभी प्रधान मंत्री से उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम अमुक व्यक्ति के काम से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रधान मंत्री ने सदा यही कहा कि यहां के विधायकों के द्वारा मुख्य मंत्री को परिवर्तित करने का अधिकार है, उन पर मैं अपनी बात नहीं थोपना चाहता। लेकिन आपके यहां एक आदमी को थोप दिया गया और आपने उसको स्वीकार किया। कमसे कम जनता पार्टी में यह सब नहीं चल रहा है, इससे आपको सबक सीखना चाहिये। हमारा मुख्य मंत्री नारायणदत्त तिवारी की तरह संजय गांधी की चप्पल उठाने वाला नहीं होगा। हमारा मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी और ज्ञानी जैल सिंह की तरह नहीं होगा हमारा मुख्य मंत्री विधायकों की भावनाओं का प्रतीक होगा और जब भी वे उस पर अविश्वास प्रकट करेंगे, तो निश्चित रूप से उसको जाना पड़ेगा। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसको इन लोगों को सीखना पड़ेगा।

मैं श्री स्टीफन साहब को कायदे का आदमी समझता था। उनके विरोधी पक्ष का नेता बनने से पहले यह अहसास होता था कि उन्होंने जो गलतियां की हैं, उन्हें वह स्वीकार करते हैं। लेकिन जब से वह विरोधी पक्ष के नेता बने हैं, तब से उनके रुख में परिवर्तन हो गया है। अब वह बार-बार कहते हैं कि आपातकाल सही था और इस देश को केवल मिसेज गांधी ही बचा सकती हैं। मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस देश में जो इतना बड़ा पाप हुआ है, वह अपने आप को उसमें शामिल न करें। हिन्दुस्तान में अब मिसेज गांधी कभी भी सत्ता में वापस नहीं आने वाली हैं। अब वह इस बात को समझ लें और इस राग को अलापना बंद कर दें। बार-बार इन बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है।

जहां तक देश की समस्याओं का प्रश्न है, आप भली-भांति जानते हैं कि इस बीच में प्रकृति का प्रकोप इस देश पर हुआ। इतनी भयंकर बाढ़ आने के बावजूद हिन्दुस्तान में चहुंमुखी विकास हुआ है और जितना भी कार्य हो सकता है, वह सरकार ने करने का प्रयास किया है। मैं इस सदन की तरफ से उन सभी संस्थाओं और मित्रों का हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने बाढ़ के समय आगे आ कर लोगों की सहायता की और इस देश को एक विकट संकट से उबारा।

माननीय सदस्य ने हमारी सरकार की नीति के बारे में कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नीतियां और नीयत दोनों साफ़ हैं। इन लोगों की नीतियां भले ही ठीक हों, लेकिन इन की नीयत ठीक नहीं है। इस लिए इन्हें हमारी नीतियों की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। यह इस देश की पहली सरकार है, जिस ने हिन्दुस्तान के गत इतिहास को दृष्टि में रखते हुए यह महसास किया है कि कृषि को हिन्दुस्तान के विकास का प्रमुख साधन बनाया जाये। इसी लिए उसने कृषि की उन्नति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आपको जानकारी है कि विगत तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में सिंचाई पर 530 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे, जबकि अब 890 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जो कि पहले से दुगनी रकम है।

इस के अतिरिक्त किसान जो कुछ पैदा करता है, और जिन चीजों को किसान खरीदता है, उनमें सरकार एक तारतम्य स्थापित कर रही है।

आज हमें इस बात पर बड़ा घमंड है कि हमारी सरकार किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं करती है। वी आर नाट पैरासाइट्स। आज हमारे देश में इतना खाद्यान्न है कि सरकार को किसी दूसरे देश से गेहूं मांगने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक उपभोग की चीजों पर भी नियंत्रण हुआ है .....।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य आठ मिनट तक बोल चुके हैं। अब वह समाप्त करने का प्रयत्न करें। और भी बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रामजी लाल सुमन : मैं कह रहा था कि आवश्यक उपभोग की चीजें लोगों को उचित मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं। देश के 5004 ब्लाकों में से 2300 ब्लाकों को अत्योदय योजना लागू करने के लिए चुना गया है। इस योजना के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि समाज के अन्त के लोगों का —सब से कमजोर व्यक्तियों का—उदय हो। काम के बदले अनाज देने की योजना भी एक अच्छी प्रक्रिया है, जिससे लोगों को राहत मिलगी।

श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज के सम्बन्ध में जो कमेटी बनी थी, हमें उसकी रिपोर्ट पर नये सिरे से विचार करना चाहिये, ताकि देश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। एक जगह पर सत्ता इकट्ठा होने से जो दुष्परिणाम होते हैं, उससे हम परिचित हैं। इस लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे नीचे से ले कर ऊपर तारतम्य स्थापित हो। प्रधान मंत्री ने बार-बार मुख्य मंत्रियों की बैठक बुला कर कानून और व्यवस्था बनाये रखने पर जोर दिया है। भूमि-सुधारों के सम्बन्ध में भी प्रधान मंत्री जी कहते रहते हैं कि राज्यों को तत्काल इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये।

जहां तक कुटीर उद्योगों का सवाल है बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है और अब तक 250 ऐसे केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान कर गई है जो एक खुशी का विषय है। विकास के कार्यों

(श्री रामजी लाल सुमन)

का जहां तक सम्बन्ध है, 1 हजार से अधिक आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है और हर गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य यह सरकार कर रही है।

परिवार नियोजन का जहां तक सम्बन्ध है इस देश में एक मनोवैज्ञानिक वातावरण ऐसा तैयार हो गया था कि परिवार नियोजन एक बुरी चीज है क्योंकि जहां जायज लोगों का परिवार नियोजन होना चाहिये था वहां कुछ ऐसे लोगों को भी आप ने बेकार कर दिया जिस की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए हिन्दुस्तान में नये सिरे से एक मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया जा रहा है कि छोटा परिवार ही उत्तम है और इस दिशा में सारे काय किए जा रहे हैं।

हमारे प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि इस देश की शिक्षा नीति में परिवर्तन लाया जायगा और निश्चित रूप से आग आने वाले समय में यह जो सड़ी गली शिक्षा नीति है उस का खात्मा होगा।

मुझे एक मिनट केवल और लेना है। मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं नैपाल में दो लोगों को तत्काल फांसी दी गई है और वह सिर्फ इसलिए कि वहां प्रजातांत्रिक और समाजवादी मूल्यों की इतिश्री हो जाय। मैं सम्मानित सदन के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि चाहे वह नैपाल की सरकार पर मनोवैज्ञानिक असर डाले या चाहे कुछ भी करे लेकिन जहां जहां जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो रही है, हिन्दुस्तान की सरकार को उन सब लोगों को समर्थन देना चाहिये। समय कम है। म आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री महामाया प्रसाद सिंह (पटना) : सभापति महोदय, मैं बीमार आदमी हूं इसलिए बैठ कर बोल रहा हूं और आप ने भी इजाजत दी है, इस के लिए मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

जो भाषण राष्ट्रपति जी का हुआ है उस के लिए मैं उन को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इस बात के लिए उन को बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा है कि चीन वियतनाम सीमा पर अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं उन से अन्तर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व को जो खतरा पैदा हो गया है उस से हम गंभीर रूप से चिंतित हैं। लड़ाई तत्काल बन्द होनी चाहिये और पहला कदम यह हो कि चीन की फौजें वियतनाम से हट जायें। इस के लिए मैं उन को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही काफी होशियारी का काम किया है और कोऑपरेशन दिखलाई है चीन के बरखिलाफ यह आवाज उठा कर। मैं उन को धन्यवाद देता हूं।

साथ ही साथ मैं श्री जत्ती महोदय को भी जो वाइस-प्रेसीडेंट हैं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हिन्दी में राष्ट्रपति जी के भाषण का अनुवाद सुनाया। इस के लिए वह हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

यहां पर इसलिए नहीं बोलने के लिए खड़ा हूं कि मैं कोई आलोचना करूं। राष्ट्रपति जी के भाषण में जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उस की ताईद करता हूं और मुझ को विश्वास है कि उन के प्राइम मिनिस्टर, माननीय मोरारजी देसाई अच्छी तरह से गांधी जी के रास्ते पर काम करेंगे। पर साथ साथ मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस भाषण में गांधी जी की बात नहीं है। साथ ही मोरार जी देसाई ने जो नशाबंदी की बात की है उस पर भी जोर नहीं दिया गया है। यह होना चाहिये था। स्टीफेन साहब की ताईद मैं नहीं करता हूं। उन की पार्टी का मैं नहीं हूं। मैं तो जनता का हूं और जनता का रहूंगा और हमारे और जनता के बीच में कोई भेदभाव नहीं है

उठ गया परदा दुई का दमियां से देख ले।
अब तेरी तस्वीर मैं हूं तू मेरी तस्वीर है।

जनता और हम में फर्क नहीं है। मगर स्टीफेन साहब को शायद फर्क मालूम पड़ता हो। फिर भी एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जहां तक ला एण्ड आर्डर का सवाल है, बिहार को ही ले लीजिए, बिहार में क्या हो रहा है ? बिहार की हालत बहुत नाजुक है। अंग्रेजों ने तो हिन्दू और मुसलमानों को लड़ा कर राज्य किया और उसकी हम निन्दा करते हैं। जब हम अभी पटना से चलने लगे तो प्रोफेसरों ने आकर मुझे से कहा कि यहां घर घर लड़ाई हो रही है, जात जात की लड़ाई हो रही है, शहर शहर की लड़ाई हो रही है, नगर नगर की लड़ाई हो रही है, डगर-डगर की लड़ाई हो रही है और रास्ते-रास्ते की लड़ाई हो रही है। किस लिए ? मैं यहां पर डिमोक्रैसी की दुहाई देने के लिए नहीं आया हूं। हम डिमोक्रेट हैं, हमने डिमोक्रैसी की रक्षा की है। उन लोगों के चंगल से डिमोक्रैसी की रक्षा करके यहां पर जनता की सरकार कायम की है। फिर भी मैं आप से नम्र निवेदन करूंगा कि यह जो बिहार में दिन दहाड़े खून होते हैं, प्रोफेसर मारे जाते हैं, अच्छे आदमी मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, स्त्रियों का स्त्रीत्व नष्ट किया जाता है उसके सम्बन्ध में भी राष्ट्रपति जी को कुछ कहना चाहिये था।

साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि बिहार में एक तरह की अराजकता है। यू० पी० में भी सुनते थे कि अराजकता थी। मैं किसी दूसरे प्रदेश के बारे में कहना नहीं चाहता, मैं अपने प्रान्त के बारे में कहना चाहता हूं। अंग्रेजों के हिन्दु-

इस्लाम पर राज्य किया, कई सौ वर्षों तक, हिन्दू मुसलमानों को आपस में लड़ा कर लेकिन हम यह नहीं करना चाहते। हमको ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे आपकी द्वेष तथा ईर्षा मिट जाये और हम सभी एक हो कर हिन्दुस्तान को प्रजातन्त्र के रास्ते पर ले चले और दुनिया के सामने एक मिसाल बना कर खड़ा कर दें।

इसके अलावा गांधी जी की बहुत सी बातें हैं जो कि होनी चाहिये थीं लेकिन वह नहीं हुई जिसके लिए मुझे दुःख हैं। वह बातें यदि रहतीं तो आज हमारी छाती फूली नहीं समाती। तब हम स्टीफेन साहब से कह देते कि यह प्रजातंत्र है और हम गांधीवादी हैं, हम गांधी जी के रास्ते पर चल कर हिन्दुस्तान को आजाद रखेंगे। लेकिन अफसोस है कि आज गांधी जी की बातों से हम दूर निकल गये हैं। लेकिन मैं क्या कहूं :

ए मेरे जख्मे जिगर, नासूर बनना है तो बन
क्या कहूं इस जख्म पर मरहम लगाना है मना।

इसलिए मैं धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए, अभिनन्दन करते हुए गांधी जी के रास्ते पर चलने के लिए सभी से आग्रह करूंगा, करता रहुंगा और राष्ट्रपति जी के कदमों में भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी रीति और नीति रखें जिससे यह देश गांधी जी के रास्ते पर चल कर संसार में एक मिसाल कायम करे और हम सभी आपस में मिल जुल कर काम करें। केवल इतना ही आज मुझे कहना है, ज्यादा नहीं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Saugata Roy, your party has been allotted one hour and 30 minutes. You should try to confine yourself within this time.

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): I will speak for half an hour.

MR. CAIRMAN: Now you cau start.

SHRI SAUGATA ROY: Mr. Chairman, Sir, on behalf of the Congress Party in Parliament, I rise to oppose this Motion of Thanks to the President's Address. If there is anything distinguished about this President's Address it is in the fact that it is most undistinguished. If there is anything noteworthy in the President's Address, it is in the fact that there in nothing noteworthy in the Presiden's Address- It is like a publication published by the DAVP, a patch work of different things sent by different Ministries to the President. This does not reflect the state of the nation at all, this is not an honest appraisal of the state of the nation at all and I am sorry to say that it has deprived the President of his personal honesty. Is it not the same President who has gone on record saying in public that he was distressed to see every day somebody was being fired at? Is it not the same President who, though his government did not appeal for clemancy for Bhutto, went on his own and appeared for clemency to Bhutoo? It it not the same President who unveiling a portrait of Rajaji in the Central Hall said that Rajaji did not have any 'son problem', the present government probably had? Is it an honest appraisal? Does it bring into focus the the tensions that had been building up in society is it forward-looking? Let say that it is not. Unfortunately our President has totally folowed the letter the address prepared by his Government. A discussion on the President's Address, I know, is not actually a discussion on the opinion of the President. It is a discussion on the performance of the government. I want to remind this government that in their time they will have five President's address; with this three are over; only two more are left. They have done a major part of their job now it is time for the furture. In the first year they were doing away the emergency excesses. Here also the President's Address mentions the 45th amendment to the Constitution. Nowhere does it mention that the Opposition totally cooperated with the government in passing the 45th amendment. It mentions special courts. I have no objection to special courts being set up. But has not Justice Krishna Niyer in his judgement said that special courts should not only be limited to emergency excesses, to those who committed excesses but also extended to cover all those in high positions. Does the proposed Bill bring forward this fact? It does not. The government must give strenth to the political, social and economic life in the country. The President's Address

[Shri Saugata Roy]

shows that this is a lack-lustre government. Even after three years the janata government does not have a coherent philosophy, coherent guidelines. That is why the President's address is a patchwork; the government itself is a patchwork; its policies are a patchwork and the bureaucracy is a patchwork. Government should be forward looking and it should plan for the 21st century, for the future generation. Here we have a government of obscurantists, of faddists, people who live with their fads and who will go to grave with their fads, leaving millions of people unemployed in this country. It is with this thought that I open my comments on the President's Address.

I am sorry that the President's Address has gloated over tensions that have grown in this country. Nowhere has it mentioned about the communal riots that took place in Aligarh or that RSS people butchered innocent Muslims; nor does it mention about the atrocities committed on Harijans all over the country, especially in North India. It has failed to mention that regional tensions are again on the rise. It has failed to mention the gruesome incidents on Assam-Nagaland border where a large number of people were killed in broad daylight, not by outsiders, within our own territory. Nor does it mention about the tension that exists in the crucial border state of Jammu and Kashmir where the people of a whole region are up in arms against a dishonest government fighting for correcting the regional imbalances. It does not mention all these things anywhere.

On the other hand it gives a very rosy picture on the economic front. Before discussing the economic front, I ask: can this government claim to function as a government? Don't you remember that in June 1978, after Mr. Charan Singh was sacked, in this Parliament we discussed his correspondence in which he said that he was surrounded by corrupt men? Don't we remember that on the day before the kisan rally Mr. Charan Singh, the present Deputy Prime Minister made a statement on the floor of this House that the Prime Minister had treated him like a servant, and that the relationship between the Prime Minister and his cabinet colleagues was master-servant relationship? The same Mr. Charan Singh is back in the Government. The President says, well, Mr. Charan Singh is back in the Government and all is right with the world. It is not.

Mr. Chairman look out, everything is not right with the world. Even in Delhi, on the D.T.C. Bus fare issue, when people were agitating, the police lathi charged the innocent students including the girl students of Jawaharlal Nehru University. Nobody has said a word about it. About the plight of the refugees at Marichati where innocent Dandakaranya deserters on the supposed instruction of the Central Government were being butchered by the local State Government people in West Bengal, nobody has mentioned about that. Nobady has mentioned about the residual problem of rehabiliation that exists in Dandakaranya and Marichati.

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहांपुर) इमर्जेन्सी में दिल्ली में कितने गरीबों को उनके घरों से हटा दिया गया ?

श्री सौगत राय : इमर्जेन्सी के बाद तुगलकाबाद में क्या हुआ श्री सिकन्दर बख्त ने क्या किया ? क्या इमर्जेन्सी के बाद तुगलकाबाद में डिमोलीशन नहीं हुआ? आप लोग इमर्जेन्सी की बात बोलते हैं। अब इमर्जेन्सी नहीं है, फिर भी क्या गर्ल स्टूडेन्ट्स पर लाठी चार्ज नहीं हुआ ? मैं यही पूछ रहा हूं। आप को इजाजत दी गई थी कि शासन कीजिए। आप शासन नहीं कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि कैसे शासन किया जाए ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम : सच्चाई सब को बुरी लगती है।

SHRI SAUGATA ROY: That is why, as I was saying, this Government came to power on the moral movement of Shri Jaya Prakash Narayan for establishing a non-corrupt regime in this country and this Government has failed to give the country a clear line on the corruption issue.

On the Kanti Desai issue the Prime Minister has not till today agreed to the Rajya Sabha Resolution to refer all the charges against Kanti, though it has been raised on the floor of both the Houses, to the Chief Justice of the Supreme Court.

I do not say that Kanti is guilty. People say that he has built a house in Ahmedabad and he has shares here and there. All that I wanted is that the Prime Minister should have referred it to the Chief Justice of the Supreme Court. Three days have passed but he has not done so. They say that the condition of the country is good and people have faith in Government.

Before me the Leader of opposition, Mr. Stephen, dealt at great length the economic situation. I shall not go into the details of the economic situation. But it seems that the Government has gloated over the fact that last year we had production of 25 million tonnes of food grains. All right, so far so good. But what happens to the farmers? To-day Rice is selling at Rs. 40.00 per quintal in Tamilnadu. Sugar cane is selling in Andhra Pradesh at Rs. 7.00 per quintal. This Government is supposed to look after the rural economy. The leader of the Kisan, Mr. Charan Singh, is in the Government and this is the deal that you are giving to the poor kisans. When there was slump in the price of wheat in the North, Mr. Charan Singh said, the Food Corporation went forward to purchase. Now when there is slump in the price of rice in the whole of South India, in the price of sugar cane, this Government does not go forward. The Food Corporation does not ago forward. The farmer does not get relief.

Again you say that you will reduce unemployment. You are taking great strides to solve unemployment. I quote from the recent survey of a book made by Prof. P. R. Brahmanand. This is the finding of Prof. P. R. Brahmananda on the famous book 'Planning for a Futureless Economy':

> "Prof. Brahmananda finds on an examination of the detailed data from 60 regions in India, that many of the Janata Plan's promises are invalid. Thus for example, improvements in per hectare productivity of crops does not significantly affect rural unemployment. Similarly rural electrification and rural roads do not affect rural unemployment significantly. The provision of house hold industries is negatively correlated with rural employment. The staggering implication of these findings is that many of the leading hypotheses of the Janata Party's New Economic Strategy are not merely invalid but there is the possibility that the pursuance of this strategy, in the absence of other countrevail ing elements will lead to worsening of the employment situation....."

You say that you have gone in for rural employment. Let me ask the Prime Minister. Ten years hence what will happen to him, I do not know.

The Prime Minister has promised that he will wipe off unemployment from the country. Can he give to the people of this country any figures to say how much unemployment has been wiped off. But I have got figures to show that unemployment has not declined. In fact, both on the live register and people who are not on the live register, unemployment has shown an increase and this so-called money spent in rural areas will have only a marginal effect on the total question of unemployment.

[Shri Saugata Roy]

The Janata Party has coined a few new slogans like rolling plan, small technology, rural industrialisation, prohibition, etc. These have become facades of inaction as well as ineffective governance. This country is being governed badly economically and the rolling plan is a plan for a futureless economy. Government have to be reminded that in twenty years, the population of this country will reach the 100 crore mark and in twenty years, the number of unemployed in this country will become 120 million or 12 crores. What is the projection in your plan? Your sixth plan says that you will do a big leap forward in wiping out unemployment. As a famous economist, Dr. Wagle has pointed out, Mr. Morarji Desai has promised to overcome unemployment within a decade and raise the living standards of the poorest. The Sixth Plan draft has gone a stop ahead and has even provided for an employment rate which will not only absorb the annual additions of about five to six millions to the labour force but also take care of a substantial part of the backlog of 20.6 millions unemployed in the country. Over the past 21 months, however, there has been no spurt in employment, no upturn in capital formation. In fact, the available jobs, being relatively few, are easily engulfed in a rabid controversy of priorities and reservations. "So, the Government has a small cake to offer and now it is making us fight for that small cake. Reservationists and anti-reservationists, Muslims and Harijans, ex-servicemen and other unemployed persons are made to fight for that small cake and the Government has not introduced any new employment. Mr. Fernandes thinks that his plan for district industrial centres is the be-all and end-all. I would like to tell him that in the last one year, one thousand foreign collaboration plans have been approved. In the last one year, Birlas have been given an increasing number of licences. I would like to refer to the famous—BHEL agreement, entered into with Siemens. There is need to ensure that any foreign collaboration into which the BHEL is entering does not erode the technological and scientific base of one of the most dynamic and successful enterprises—the Public Sector—nor blunt its thrust towards self-reliance. Mr. Fernandes has got love for Siemens and he has got love for foreign collaboration. The Industries Minister is not Minister for India but he is Minister for Libya and West Germany where he spends most of his time, when he is not in Chikmagalur.

I would like to mention that in the last one year, the economy has shown a sharp downward trend. During the last 10 years our exports were going up and up. Last year was the only year in which the exports had gone down. You say, you have a comfortable balance of payment. But it is not because of you but because of the poor people who are working in the Gulf countries and sending all their remittances to this country. Otherwise, today you are importing anything and everything. If there is a slight rise in the price of rubber, you import rubber. If there is a slight rise in the price of oilseeds, you import oilseeds, as a result of which your foreign exchange reserves get depleted and the domestic farmer does not get a proper price for his produce. This is the mad import policy that the Janata Party is pursuing. Import anything and perish while not exporting! This is what you are doing today in your management of the economy.

I now come to the other important thing. The President has very glibly mentioned "The Industrial Relations Bill now before Parliament constitutes a comprehensive approach to the establishment of sound labour-management relations. The Bill deserves earnest and early consideration by hon. Members." I am sorry

and shocked to see that about a Bill which has been opposed by all trade unions, by all sections of industrial labour unanimously, the President says that it deserves earnest and early consideration. What is the situation on the labour front? We had a strike on the dock front which continued for 30 days. We had a jute workers strike in West Bengal involving 2.5 lakh workers, which continued for 48 days. The textile workers have threatened to go on strike from 15th. In the whole coal industry, the workers have given notice of a strike. What does this Government do? It gives us platitudes that they will bring the Industrial Relations Bill for the benefit of the labour. The President Address does not take into account the increasing labour unrest in this country. You cannot go on saying that it is the Emergency backlog.

Again on the front of population Control, today in this House, Mr. Rabi Ray admitted that on the front of population control, there has been a sharp decline in the last two years when Mr. Raj Narain was the Health Minister. He said that he wanted to tone it up. He openly admitted that there was a set back. Today unless something is done on this issue, the country will soon reach an explosion point. As I mentioned, by the year 2000, we will be one hundred crore, strong. Is the country in a position to feed such a large number?

Now I will come to the more important line i.e. science and technology. Today the scientists and technologists in this country believe that this Government is a Government of backward looking people, of faddists and science and technology is going to the dogs. The best Scientist in the country who was responsible for the Pokaran explosion, Dr. Ramana, has been sent to the dog house in the Defence Ministry, taken off from the Atomic Energy Commission. The Prime Minister has his own favourite and apologetic scientist, Dr. Atma Ram. He is a formaldehyde Chemist who poses as a big scientist. He has gone ahead and said that the Electronics Commission is no good, we will wind it up. All along, scientists are committing suicide in the Indian Council of Agricultural Research. They are feeling desparate and despondent. This is mainly because of the Prime Minister's backward looking policy on the nuclear issue.

Who has heard of a Prime Minister who goes to a foreign country, waits there for four days to meet the President of that country? Then he goes to the United Nations and without anybody asking him, he declares that India is not going to make any nuclear explosion. Nobody has asked him. He mages this statement voluntarily. I want to ask him: did the country or the Parliament or his own Cabinet give him permission to make such a statement? Today, we know that for Tarapur also, the uranium fuel shipment is pending. This Government has no courage to speak openly that we will break down the treaty obligation, contractual obligation with the United States. Over and above that, we have been fed a sweet pie by Carter. The Prime Minister without asking anybody has again allowed a joint panel of Indo-US scientists to go into the question of full scope safeguards. Yesterday in reply to a question he said that this joint panel is under negotiation. They will inspect all our nuclear installations. It is for the first time foreigners will be allowed to inspect our nuclear installations. This is the self-respect this Prime Minister has given to the country. Whatever little we have built up, whatever our scientists and technologists have built up through their effort, today that prestige and self-respect is being undermined by the off hand and off the cuff remarks by the Prime Minister, not only about Pondicherry but also about the nuclear policy, which affects the whole nation.

[Shri Saugata Roy]

Government have waxed eloquent about the success of our foreign policy. I would say that nowhere has the failure of the Government been more evident than in the field of foreign policy. The Government have failed to take note of the rising mass upsurge in different countries of the world. The Government have no eyes to see. They have failed to take note of the mass upsurge in this country and also in Pakistan that we should ask for clemency for Mr. Bhutto from Mr. Haq. This Government have not responded to the appeals of so many Members of Parliament to ask for clemency for Mr. Bhutto.

When there is a coup in Afghanistan. Shri Vajpayee rushes post has to the Shah to assure him that India supports the new regime and that the relationship with Iran will not be disturbed. When the Shah abdicated the position and made Bakhtiar the Prime Minister without asking anybody, he sends a letter congratulating Bakhtiar on becoming the Prime Minister. How long did he last? He has gone and Mr. Bazargan has come. I yesterday saw that the Indian Ambassador has gone there and eulogised the new regime. What was the need for congratulating Mr. Bakhtiar? There was no need. But this Government does not see, this Government does not understand. This Government, again, failed to recognise the revolutionary regime in Kampuchea.

16 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

This Government thought it can bring about a thaw in India-China relations. I would be the first to support any move if India-China relations were sought to be improved. But this visit to China was a publicity gimmick and it is only to give a dramatic flair to the activities of Shri Vajpayee. If Shri Vajpayee went to China to improve our relations, I want to know what is the result of his visit. Has he solved a single one of our border problems? Have we got back Manasarover? Has he solved any single outstanding issue?

AN HON. MEMBER: He has got noodles.

SHRI SAUGATA ROY: This Government does not see the changes that are taking place all over the world. We have surrendered ourselves to Carter's diplomacy and allowed the inspection of our nuclear installations and thus we have lowered the prestige of India abroad.

Then he goes to China and does not know that China is going to attack Viet Nam. He says "I was in Hangchou, how could I know?" It is the business of the External Affairs Ministry to know it; it is the business of the Indian Ambassador to know it. But this Government does not open its eyes. As one of my colleagues said in Parliament so well, it is the Prime Minister who makes the foreign policy, the Foreign Secretary implements it and Shri Vajpayee translates it into Hindi. This is the way this Government goes on.

So, as I have said, this President's Address does not give any realistic picture of the actual situation obtaining in this country, nor does it project the future for the country. I would again remind the Janata Benches that this is the third President's Address and you will have only two more.

SHRI A. BALA PAJANOR (Pondicherry): Are you sure?

SHRI SAUGATA ROY: Either you improve or perish; the maximum you have got are two more.

The moment Shri Charan Singh comes back here in the Cabinet, the

drama starts in U.P. The moment that drama is over, it starts in Bihar and once it is over in Bihar, it starts in Himachal Pradesh. This is not the way to run this country, this is not the way to govern this great country. For that you need foresight, some amount of cohesion and you have to be forward looking. Unfortunately, that is lacking in the approach of the Government and that is why this Government is showing miserable failure on all these fronts.

With these words, I again oppose the Motion of Thanks to the President for his Address.

श्री धर्मवीर वशिष्ठ (फरीदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहुत चर्चा हुई है। हमारे अपोजीशन के साथी स्टीफेन साहब ने लगभग पौन घंटे तक काफी बातें कहीं। उस में एक प्रमुख बात यह कही कि चौधरी चरण सिंह को मोरार जी भाई ने वापस ले लिया जिन्होंने इतनी सारी बातें करप्शन की बतायी थीं और उन्होंने यह कहा कि हरिजनों के ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ, सोशल टैंशन बढ़ गई। इन दो तीन बातों पर मैं खास तौर से हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

बहन इंदिरा गांधी जी ने बहुत खुल्लमखुल्ला यह बात कही है कि हम जनता पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं, हकूमत मजबूत रहनी चाहिए, उस को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, शायद उसी इरादे से ये काम किए गए कि एक गुलदस्ता जेल से भेजा गया कि किसान सम्मेलन में पहुंचे। उसी इरादे से यह भी किया गया कि एक नवासे की, बच्चे की पैदाइश हुई चौधरी चरण सिंह जी के यहां तो तुगलक रोड पर भी वह पहुंच गई जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। ऐसे ही मजबूत करने का ख्याल इन का है। अब अंगूर खट्टे हैं, वह बात तो हाथ नहीं आई। एक बार रेल में दो आदमी जा रहे थे एक बुजुर्ग था, एक लड़का था। लड़के ने कहा कि बुजुर्ग महोदय, कहां जाओगे? कहा बम्बई जाऊंगा। कहा मैं भी बम्बई जाऊंगा। फिर कहा कहां से आ रहे हो? दिल्ली से। अरे भाई, कमाल हो गया मैं खुद भी दिल्ली से आ रहा हूं। दिल्ली में कहां रहते हो? कमला नगर में। भाई वाह, मैं भी कमला नगर में रहता हूं। कमला नगर में कहां रहते हो? 119 डी में। अरे भाई, कमाल हो गया, मैं खुद भी 119 डी में रहता हूं। तो जो और सवारियां बैठी हुई थीं हमारे अपोजीशन के साथियों जैसी, उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने कहा यह क्या तमाशा बना रखा है? उन्होंने कहा इस में तमाशे की क्या बात है, हम बाप बेटे वक्त काट रहे हैं, इस में आप को क्या तकलीफ है? तो भाई भाई कभी अलग हो जांय, कभी मिल कर बैठ जांय इस में आप को इतना क्या हो

गया जो आप इस बात को लेकर चल पड़े। लेकिन मैं पूछता हूं कि यह जो चीज है यह क्यों है? इस की वजह और गहरी है और यह गहरी वजह यह है कि चरण सिंह जी का वापस यहां लौटना बहुत बुरा हुआ। अब तो उन के सब ख्वाब खत्म हो गए। उधर दूसरी तरफ वह जो झूठी मूठी बात दो कांग्रेस में चल भी रही थी वह भी खत्म हो गई। तो इस से बुरा दिन कौन सा होगा? चरण सिंह जी का आना और स्वर्ण सिंह का जुतमपैजार करना, इस से बुरा दिन कोई हो नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने "ग्रोथ-रेट" की बाबत जिक्र किया। वाह, क्या बात है, कहां पसीना माथे पर आया है—

सब उन पे है तसद्दुक, वह सामने तो आयें,

शोलों से भी जो खेलें, दामन को भी बचायें।

ग्रोथ रेट की बाबत उन्होंने कहा—लेकिन उन्होंने खुद पिछली पांच योजनायें पूरी करने के बाद इस देश को कभी भी 3 परसेन्ट से ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं दिया, बल्कि "जीरो" पर भी पहुंच चुके थे, लेकिन आज वह ग्रोथ रेट की बाबत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इस लिये कि वह चरण सिंह जी की सरकार में आना मुनासिब नहीं समझते हैं। वह जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह आ जायेंगे, फाइनेन्स मिनिस्टर हो जायेंगे तो जरूर किसानों को फायदा पहुंचाने की बातें बोलेंगे और हम ने जो 30 सालों में गल्तियां की हैं, वे हमारे सामने आयेंगी। उन में से एक तो प्लानिंग की बात है—यह हमने रूस से सीखा है कि कैपिटल गुड्स को बढ़ाने पर जोर दिया जाय। लेकिन, जनाब, रूस की स्थिति दूसरी थी, यानी उन के यहां भूख की बात नहीं थी, फूड-प्राबलेम उन के सामने नहीं थी, इसीलिये उन्होंने इण्डस्ट्रीज पर जोर दिया, लेकिन हमारे यहां तो फूड-प्राबलम बेसिक प्राबलम थी। तो फिर 30 सालों की प्लानिंग का क्या नतीजा हुआ? एक गांव में एक आदमी की आमदनी 1960–61 में 419 रुपये थी, जो 1975–76 में घट कर 392 रुपये रह गई स्टैण्डर्ड प्राइस के आधार पर। लेकिन इस के मुकाबले शहरों में क्या हुआ? 1960–61 में 392 रुपये आमदनी थी जो बढ़ कर 822 रुपये हो गई। यह जो उल्टी गंगा बह रही थी कि शहरों की आमदनी बढ़ रही थी और गांवों की घट रही थी, उस को रोकने की बात चौधरी चरण सिंह आकर कहना चाहते हैं और यही उन की ज्यादती का कारण है।

आज उन को हरिजनों का ख्याल आ रहा है कि इस हुकूमत के दौरान इतने हरिजन मारे गये—बहुत खूब। हम इस बात को मान कर चल रहे हैं कि उन की ज्यादा से ज्यादा हिफाजत होनी चाहिये, लेकिन कई युग पीछे या पिछले 30 सालों में क्या ऐसा नहीं हुआ है जिस में हरिजनों या दूसरे कमजोर वर्गों के साथ इतना ही या इस से भी घना अत्याचार नहीं हुआ है? अगर वक्त हो तो मैं उन सब की मिसालें भी दे सकता

हूं, लेकिन मैं उस की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि वे इन को खूब जानते हैं। क्योंकि मुझे यह भी पता है—

जो चुप रहेगी जबाने खंजर,
लहू पुकारेगा आस्तीं का ।

इन्हें सब पता है, इस लिये हरिजनों की बात को यहां पर लाना गलत है। उन को पता है कि उन्होंने हरिजनों का कितना फायदा किया है और उस का मेरे पास सबूत भी है—हरिजनों के एक नेता जो तीस सालों से इन के साथ थे—बाबू जगजीवन राम—उन्होंने यह महसूस किया कि इन के यहां न लोकतन्त्र है न हरिजनों की रक्षा है, न किसी गरीब को उठाने का मकसद है—इसलिये वह भी आप को छोड़ गये। इस लिये आप का हरिजनों की बात को उठाना गलत है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं—यह जो राष्ट्रपति जी ने अपना एड्रेस पेश किया है—कुछ लोगों ने कहा कि यह राष्ट्रपति बेचारे की परसनल बात नहीं है। आप की यह बात ठीक है। हम ने पश्चिमी जम्हूरियत से यह सीखा है कि पहले राष्ट्रपति से भाषण करवायें और उस के बाद उन को थैंक्स दें और उस में उन के खिलाफ़ उल्टा-सुल्टा कहें। मैं भी यही समझता हूं कि उन को बीच में लाना ठीक नहीं है। उस का मतलब यही है कि राष्ट्रपति जी ने सरकार की बात आप के सामने रख दी है और सरकार उस के बारे में जवाब देगी। राष्ट्रपति जी ने जो कहा है वह सरकार की ही बात आप के सामने रखी है।

मैं एक-दो बातें और आप से अर्ज करना चाहता हूं—स्टीफन साहब इस वक्त मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहा कि अप्रैल, 1976 से इन्वेस्टमेन्ट में कोई फर्क नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं—पहली योजना में खेती पर 37 परसेन्ट खर्च किया गया था, दूसरी योजना में 17.3 परसेन्ट और उस के बाद जब तक कांग्रेस सरकार यहां रही, 23 परसेन्ट से ज्यादा कृषि पर, सिंचाई पर और दूसरी एलाइड-चीजों पर खर्च नहीं किया गया। इस के मुकाबले में पहली प्लान में 4.9 पर सेन्ट खर्च किया गया था, उद्योग और खान पर, दूसरी में 24 पर सेन्ट और उस के बद कभी 23.7 पर सेन्ट से नीचे नहीं रहा। इस से बराबर ऊपर ही चढ़ता रहा है। 1974-75 में उन का उस पर 22.6 पर सेन्ट खर्चा था, 1975-76 में 27.5 पर सेन्ट इंडस्ट्री पर और 1976-77 में 276.82 पर सेन्ट खर्च था और इस क मुकाबले में कृषि पर बराबर गिर रहा था और वह 1974-75 में 21 पर सेन्ट, 1975-76 में 19.4 पर सेन्ट और 1976-77 में 20 पर सेन्ट था। इस के मायने यह हुए कि 1975-76 और 1976-77 में कृषि से 41 पर सेन्ट ज्यादा इंडस्ट्री पर खर्च किया गया था और 38 पर सेन्ट दूसरे साल में किया गया था। आप जानते ही हैं कि पिछली सरकार ने बड़े से बड़े मामले में देश हित को नहीं देखा। एक-चौथाई भूमि जो सायल इरोजन और कटाव से बर्बाद हो जाती थी, उस को रोकने के लिए सन् 1951 से 1973 तक यानी 23 साल में केवल 47 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये थे। इस तरह की दूसरी बहुत सी बातें हैं जिन पर उस सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

मैं एक बात और बताता हूं। इस्पात का उत्पादन पांचों सालों रहा चौथी प्लान में और की कैपेसिटी की उस के 36 पर सेन्ट कम रहा। फिर ढाई हजार करोड़ रुपया 1974-79 के लिए और रखा गया, फैमिली प्लानिंग के लिए रखा गया कस के तरीके पर। आप ने कहा कि बड़ा जुल्म जनता सरकार कर रही है। आप के ख्याल में कांग्रेस (आई) के लोगों को यह इजाजत दे दी जाए कि किसी की टोपी उछालो और जो चाहे सो करो। जो कांस्टीट्यूशन में है और कानून में जो है, उस के मुताबिक काम करना चाहिए लेकिन यह याद रखिये कि हम ने देख रखा है :

लोग कांटों से बच निकलते हैं
हम ने फूलों से जख़्म खाए हैं।

हम इसे भूल नहीं सकते और इसलिए मैं यह कहता हूं कि फूल को भी ऐसी इजाजत नहीं देंगे क्योंकि हम ने फूल से भी जख़्म खाए हैं और होता यह रहा है :

जमाना देखता रहा तीरगी के सरइल्जाम।
गुनाह होते रहे रोशनी के दामन में ॥

अगर ये ज्यादा उतावले न होते और संजय राजकुमार ताज पहनने के लिए थोड़ा सा संतोष करते, तो ये कुछ दिन और बने रहते, पर एक साल में ही सब कुछ होना था। उस जल्दी में सब भूल गये। अब जो कुछ हो रहा है मोरारजी भाई और चरण सिंह का, यह बात दूसरे लेबिल की है। एक ने कुछ कहा और दूसरे ने यह माना कि यह कैबिनेट की शान की बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। ठीक बात है, डेमोक्रेसी है और यह उनका प्रेरोगेटिव है लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि चौधरी चरण सिंह बराबर डिस्सिपिलिन में हैं और कोई ऐसी बात नहीं कहते, जो देश में उथल-पुथल के लिए हो और फिर यह भी देख लिया कि किसान समाज उन के साथ है, तो उन्होंने उन को वापिस कैबिनेट में ले लिया। मैं जे॰पी॰ से 4 जनवरी को मिला था। उन को यह बताया गया था कि 5 लाख, 10 लाख, या 15 लाख आदमी किसान रैली में आए थे। कितने ही आदमी हों, मैं उस की बहस में नहीं जाऊंगा कि वह कितनी बड़ी रैली थी लेकिन असली बहस में जाऊंगा कि चाहे वे दो हजार आदमी हों या 20 हजार आदमी हों, वे बेपढ़े आदमी थे और उन्होंने कोई ऐसा-वैसा काम नहीं किया। आज हम देखते हैं कि वर्कर्स जब फरीदाबाद से आते हैं, तो हाय, हाय और मुर्दाबाद कहते चले आते हैं। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए लेकिन उन्होंने किसी की हाय, हाय नहीं की, किसी की मुर्दाबाद नहीं की। मैं ने उन से पूछा कि गांधी जी और आप ने यही तो कहा है कि वह वर्ग ऐसा है जिस में समझ तो है लेकिन अभी चेतना नहीं। अब आप यह देखिये कि उस में समझ ही नहीं बल्कि उस में जो चेतना है वह पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुकी है क्योंकि 20 लाख आदमियों ने इतनी शान्ति से प्रदर्शन किया। चौधरी चरण सिंह से श्री मोरारजी भाई नहीं चूके। लेकिन जब 20 लाख और 30 लाख किसानों को

देखा, जिन्होंने कि शांति के साथ प्रदर्शन किया था तो जनता के एक नेता को सम्मान देने की हैसियत से उन्होंने यह किया और उनको वापस कैबिनेट में ले लिया ।

आपको याद नहीं है कि जब हैदराबाद में निजाम का शासन था तो उस समय एक शाम को आल इंडिया रेडियो से यह एलान किया गया कि भारत सरकार हैदराबाद में कोई दखल नहीं देगी । लेकिन उस वक्त सरदार पटेल जो कि होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक प्लेन मंगाया और उसके पाइलट को कहा कि इसे उड़ाओ । ऊपर चल कर मैं बताऊंगा कि मुझे कहां जाना है । सुबह तक वह बात खत्म हो गयी । यह उस समय के रेडियो की खबर थी लेकिन जनता की भावनाएं कुछ और थीं । मैं आपसे कहता हूं कि जनता की भावनाओं के सामने कोई नहीं आ सकता है । आप लोग भी जनता की भावनाओं पर पैर रखना छोड़ दें । यह मैं आपको मशविरा देता हूं । अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो हो सकता है कि आप फिर सत्ता में लौट आयें क्योंकि इस देश में जम्हूरियत है । जम्हूरियत में सब लोग सत्ता में आ सकते हैं । (व्यवधान) आपने देख लिया है कि जनता की भावनाओं को कुचलने से क्या हो सकता है । हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 1977 में यह कहा था :—

"Freedom from want and freedom from fear have to be secured. We must unite against the common enemies of mankind. We dare not be timid."

साथ ही उन्होंने नान एलाइनमेंट कन्ट्रीज की मीटिंग के दो-चार दिन पहले यह भी कहा था—

"We have learnt from Gandhiji that there is no nobler quest than to work for justice and a better life for people. He taught us that dedication in the service of one's people must not be a concealed lust for power."

This is a concealed lust for power with you. It will never be a concealed lust for power with us.

जिस दिन हम लोग यह महसूस कर लेंगे कि हम लोगों का भला नहीं कर सकते हैं तो हम खुद ही सत्ता को छोड़ जायेंगे । लेकिन आप भी उस बात को छोड़ दो । आप हमारे देशवासियों की भावनाओं से खेलना छोड़ दो ।

किसी भाई ने हिन्दी और अंग्रेजी की चर्चा उठायी और कहा कि मुल्क टूटने जा रहा है । मैं जनता पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम तमिल सीखेंगे, तेलगु सीखेंगे लेकिन इस देश को नहीं टूटने देंगे । वे जब तक अंग्रेजी में बोलना चाहें, बोलते रहें, हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं होगी । लेकिन किसी के पांव उखाड़ने से राष्ट्र भाषा की उन्नति को नहीं रोका जा सकता है । हिन्दी की बराबर तरक्की होती रहेगी । साउथ वाले अंग्रेजी को इस्तेमाल करें, जब तक चाहें करें । हम न रहें, हमारे बेटे-बेटियां न रहें, पोते-पोतियां आ जाएं, लेकिन हम उन्हें अंग्रेजी का इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे । लेकिन मैं उन से यह भी कहना चाहता हूं कि वे अपनी भाषाओं को ऊपर लाएं । हम भी उनको सीखने की कोशिश करेंगे । आखिर में देश की एकता इन्हीं भाषाओं से होगी । ये सारी भाषाएं चारों तरफ से मिल कर एक सरगम बनायेंगी । साउथ के भाई मेरे भाई हैं । श्री बाला पजनौर साहब मेरे दोस्त हैं । मैं पांण्डिचेरी में उनके घर पर भी गया हूं । मैं अपने साउथ के भाइयों को बताना चाहता हूं कि हम पेट्रियट लोग हैं, हम देश के टुकड़े नहीं होने देंगे । हमने देश के लिए अपना खून बहाया है, आपने औरों का खून बहाया है । इसलिए ये सब बातें बेबुनियाद हैं ।

मैं इन शब्दों के साथ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं और कहना हूं कि जो साउथ से हमारे राष्ट्रपति जी आए हैं, वे बाराबर ऐसी रोशनी हमें बख्शते रहें ।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर (बम्बई-उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, यह भाषण सुनने के बाद हमारे जैसे लोगों को बहुत निराशा हुई क्योंकि इस भाषण में कोई भी दिशा नहीं बतायी गयी है । और हमें दुख है कि हमारे राष्ट्रपति जो एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं, और उनके ख्यालात हमें मालूम हैं, उन्हें यह भाषण करना पड़ा । यह एक बड़ी ट्रेजिडी है ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं है, इतनी कामप्लेसेंसी है कि इससे मालूम होता है कि सब कुछ हुआ है, होने वाला है और हमें कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए ।

जो देश की आर्थिक परिस्थिति के बारे में कहा गया है उसका सही चित्रण इसमें नहीं आया है । यहां तो बताया गया है कि हम रूरल इकोनामी की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, देते हैं, उनके लिए कुछ किया है । लेकिन हमें तो यह कहना पड़ेगा सरकार से कि इसके बारे में कुछ नहीं हुआ है । हमें दुख है कि देहातों में जो कमर्शियल क्रोप्स हैं उनकी कीमत गिर रही है और बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ है । उसका इस भाषण में कोई जिक्र नहीं है । अगर ऐग्रीकल्चर की समस्या सचमुच में हल करनी है तो तब तक हम जमीन की प्रोबलम को हल नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होगा । कुछ फिगर्स उन्होंने रखी हैं, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि हमने लैंड रिफार्म्स बहुत किया है और करने वाले हैं । लेकिन मेरा इस बारे में निवेदन है कि इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है । हमारे रिजर्व बैंक की रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्टस कहती हैं कि तीन करोड़ एकड़ जमीन सरप्लस है । लेकिन हमारी पंचवर्षीय योजना में कहा जाता है कि 53 लाख एकड़ जमीन हमारे हाथ में आयेगी । बाद में कहा जाता है कि 40 लाख 4 हजार एकड़ जमीन हमारे हाथ में आयी है । बाद में हमने देखा है कि उनके हाथ में 21 लाख

[श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर]

एकड़ जमीन ही आयी है । 3 करोड़ 67 लाख एकड़ जमीन सरप्लस होते हुए भी वितरित कितनी हुई है ? 12 लाख एकड़ । और यहां भाषण में कहते हैं 16 एकड़ जमीन डिस्ट्रीब्यूट की है । पता नहीं यह फिगर्स कौन देता है । पंचवर्षीय योजना कहते हैं कि 12 लाख एकड़ डिस्ट्रिब्यूट किया है, 3 करोड़ एकड़ जमीन सरप्लस होते हुए । आज एक ऐडीटोरियल मैंने पढ़ा जिसमें सरकार कहती है कि सरप्लस जमीन 10 परसेंट जमींदारों के हाथों में है, उन्होंने अपने कुत्ते और बिल्ली के नाम कर दी है । आप को ताज्जुब होगा, लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि कुत्ते, बिल्ली के नाम पर जो जमीन है उस पर भी कर्जा लिया गया है । मामूली किसानों ने तो 30 परसेंट कर्जा लिया है, लेकिन बड़े जमींदारों ने 70 परसेंट कर्जा लिया है । परन्तु खेद है कि इसका जिक्र इस भाषण म नहीं है । अगर आप सचमुच में रुरल एम्फेसिस देना चाहते हैं तो सरप्लस जमीन छोटे गरीब किसानों को मिलनी चाहिए । इसके बारे में हमारी पंचवर्षीय योजना कहती है कि हमारा जो एक्ट उसमें बदली करनी चाहिए । जमीन के बारे म जो हमारी देहात की पंचायत है और जो इंटरस्टेड हैं जमीन लेने में उनको इस मशीनरी में शामिल करना चाहिए । इस सब बातों का इस भाषण में कोई जिक्र नहीं । और जब तक आप यह नहीं करते तब तक आप कितना ही भाषण करें कुछ होने वाला नहीं है । अगर यही स्थिति रही, तो अगले साल बड़ी मुसीबत खड़ी हो जायेगी—एग्रीकल्चरल इकानोमी का कम्प्लीट कोलेप्स हो जायेगा । इस बारे में राष्ट्रपति के भाषण में कुछ नहीं कहा गया है ।

अगर सरकार वास्तव में रुरल इकानोमी को उन्नत करना चाहती है, तो उसे पहले लैंड सीलिंग एक्ट को लागू करना चाहिये । बंगाल की गवर्नमेंट ने लैंड लेजिसलेशन पास किया, लेकिन अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली है । जब भी कोई पंचायत लैंड की डिस्ट्रिब्यूशन करना चाहती है, तो बड़े बड़े जमींदार हमला करते हैं । बिहार में एक लीडर का कत्ल हो गया, क्योंकि वह आन्दोलन करते थे कि लोगों को लैंड देनी चाहिए । लैंड रूरल इकानोमी का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए उसके बारे में जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए । इस बारे में इस भाषण में कुछ नहीं कहा गया है ।

जहां तक प्राइसिज का सम्बन्ध है, होलसेल प्राइसिज के बारे में भी स्टीफन ने कहा है । सरकार कहती है कि सब कुछ सस्ता हो गया है । वह इस लिए सस्ता हो गया है कि फसल ज्यादा हुई है और प्राइसिज कोलैप्स हो रही हैं । गये दो सालों में होलसेल प्राइस इन्डेक्स जितना बढ़ा है, उतना पहले कभी नहीं बढ़ा था । सरकार की रिपोर्ट के अनुसार होलसेल इन्डेक्स 1973-74 में 139.7, 1974-75 में 174.4, 1975-76 में 173, 1976-77 में 176.6, और 1977-78 में 185.6 था । आज भी वह 185.8 है । होलसेल इन्डेक्स इससे पहले कभी इतना नहीं बढ़ा था ।

जहां तक कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स का सवाल है, 1974-75 में, एमरजेंसी से पहले दो तीन सालों में प्राइसिज सबसे ज्यादा बढ़ी थीं । तब कंज्यूमर इन्डेक्स 317 था । आज भी वह 324 है । इस का मतलब यह है कि कंज्यूमर प्राइसिज 1974-75 से भी ज्यादा बढ़ गई है । सरकार यह दिखाती है कि अनाज सस्ता है । लेकिन कपड़े का भाव कितना बढ़ गया है ? सब एसेंशल चीजों के भाव बढ़ गये हैं और उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई है और उसका जिक्र भी इस भाषण में नहीं है । टैक्स्टाइल के बारे में इतना कनसेशन दिया गया है, मगर टैक्स्टाइल मैगनेट्स भाव बढ़ाते जाते हैं । कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स के बढ़ने के माने ये हैं कि प्राइसिज बढ़ी हैं । इस बारे में भी इस भाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

हमारी इकानोमी की सब बातों के बारे में इस भाषण में काम्प्लेसेंसी दिखाई गई है । गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि दस साल में अनएम्प्लायमेंट को खत्म कर देंगे । यह बात छोड़ दें, क्योंकि दस साल यहां कौन रहेगा, यह नहीं कहा जा सकता है । लेकिन हमारे पब्लिक एन्टरप्राइजिज में, जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, अनएम्प्लयालमेंट सब से ज्यादा हो रहा है । बावेजा कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि कोलमाइन्ज में पचास हजार वर्कर्स को बेकार करने वाले हैं । केरल में कायर इंडस्ट्री में और दूसरी जगह नयी नयी मशीनरियां आ रही हैं, जिससे हजारों लोग बेकार हो रहे हैं । आज जो लोग काम पर लगे हुए हैं, वे बेकार किये जा रहे हैं । नये आने वाले लोगों की बेकारी यह गवर्नमेंट कैसे दूर करेगी । अभी पब्लिक एन्टरप्राइसेस में यह हो रहा है । बवेजा कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 50 हजार कोल माइनर्स कोल माइन्स से अभी बेकार होने वाले हैं और गवर्नमेंट ने इस के बारे में कुछ नहीं किया को बाकी को तो छोड़ दीजिए । एक यह तरीका निकाला है कि हम स्माल स्केल इंडस्ट्री चालू करेंगे तो बेकारी दूर हो जाएगी । लेकिन इस से बेकारी दूर होने वाली नहीं है । हमारा देश अब एटामिक एज में है । क्लर्क बना कर बेकारी दूर नहीं होगी तो आप कहेंगे कि विमान भी बन्द करो, रेल भी बन्द करो और बैलगाड़ी चालू करो, तो इससे बेकारी दूर होने वाली नहीं है । ''

MR. DEPUTY SPEAKER: It is now 4.30.

Mrs. Rangnekar, do you want to continue or you will take a couple of minutes more and finish?

SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR: I want to continue.

———